सुबह सवेरे

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 03 फरवरी, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 153, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

ब्लाग

आर्थिक विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा केन्द्रीय बजट

डॉ. मोहन यादव

लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं

भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में हम विकसित भारत का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 मध्यप्रदेश के लिए आर्थिक विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, उद्योगों को सरल प्रक्रियाएँ, निवेशकों को भरोसेमंद वातावरण, युवाओं को रोजगार के अवसर, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, एमएसएमई सेक्टर को संस्थागत समर्थन और नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्राप्त होंगी।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की जो नींव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रखी गई है उसे वर्ष 2026-27 के बजट ने और ज्यादा मजबूत किया है। भारत की अर्थव्यवस्था अब तेजी से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर है। युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान शक्ति और उदयमिता के सहयोग से भारत ने आगे बढ़ने जो संकल्प लिया है वह कई अर्थों में अद्भुत है। आज जब भारत औद्योगिक निवेश और निर्माण क्षेत्र का हब बनने जा रहा है, उसमें मध्यप्रदेश भी अपनी पूरी शक्ति के साथ योगदान देने के लिए तैयार है। हमने औद्योगिक निवेश के लिये अनूकूल वातावरण तैयार किया, जिससे निरंतर निवेश आ रहा है। नये बजट से पूरे इको-सिस्टम को नई ऊर्जा मिली है। बजट में हरित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया है। इससे मध्यप्रदेश को दीर्घकालिक लाभ होने वाला है। कृषक कल्याण और कृषि विकास को मिशन के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है।

इसी प्रकार सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एआई आधारित तकनीक के विकास पर बजट में ध्यान केन्द्रित किया गया है। इन तीनों क्षेत्रों में मध्यप्रदेश को हाई टेक उद्योग, डिजिटल निवेश और नवाचार आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा। इन क्षेत्रों के लिये नीतियां बनाने का काम पूरा कर लिया है। निवेश आकर्षित करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। केन्द्रीय बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। यह सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है। जिस प्रकार मध्यप्रदेश में तेजी से शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा है, नया बजट युवाओं के कौशल विकास और रोज़गार के लिए व्यापक अवसर लेकर आया है। शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम स्थायी समिति का गठन और 15 हजार माध्यमिक विद्यालयों एवं 500 महाविद्यालयों में एपीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। पर्यटन क्षेत्र में आईआईएम के सहयोग से 10 हजार गाइड्स के कौशल उन्नयन और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से अगले दशक में खेलों के परिदृश्य में बदलाव लाने का लक्ष्य युवाओं को नई दिशा देगा। महिलाओं के लिये एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए 10 हजार करोड़ रूपये का आवंटन लाभदायी होगा। युवा भारत के लिये सेवा क्षेत्र का विस्तार संभावनाओं के नये द्वार खोलेगा और रोज़गार और उद्यम के अवसर बढ़ेंगे।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदी योजना में महिला उद्यमियों को क्रेडिट लिंक आजीविका से उद्य स्वामित्व से जोड़ने में मदद मिलेगी। मध्यप्रदेश ने पहले ही इस दिशा में ठोस प्रयास किये हैं। सिटी ईकॉनामिक रीजन बनाने की नीति मध्यप्रदेश के शहरी विकास के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। शहरों को संगठित आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित करने में यह सहायक सिद्ध होगी। शहरी क्षेत्रों में नियोजित आर्थिक विकास, औद्योगिक व्यावसायिक क्लस्टरिंग और आधुनिक अधोसंरचना का निर्माण होगा। इससे मध्यप्रदेश के प्रमुख शहर संगठित आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित होंगे और निवेश अनुकूल शहरी अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। यह निवेश मॉडल मध्यप्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा और कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स तथा व्यापारिक सुगमता को व्यापक रूप से मजबूत बनायेगा।

बजट में सामाजिक समावेश पर पूरा ध्यान दिया गया है। आर्थिक विकास की ये पहल मध्यप्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। समावेशी विकास के साथ मानव-पूंजी निर्माण को भी मजबूती मिलेगी। शी-मार्ट्स, दिव्यांगजन कौशल योजना, सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल और शिक्षा कौशल आधारित पहल से सामाजिक सशक्तिकरण के साथ आर्थिक विकास को समावेशी स्वरूप मिलेगा। इससे मध्यप्रदेश में गुणवत्तापूर्ण मानव पूंजी का सृजन होगा।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को विकास के केन्द्र में रखते हुए यह बजट प्रशासनिक सरलीकरण, निवेश-अनुकूल नीतियों, संरचनात्मक सुधारों और वित्तीय स्थिरता के माध्यम से मध्यप्रदेश को तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने की ठोस आधारशिला रखता है। मध्यप्रदेश के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 केवल एक नीति-दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास का एक ऐतिहासिक अवसर है,जो मध्यप्रदेश को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में अत्यंत सहायक एवं परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी।

मणिपुर में खत्म हो रहा है राष्ट्रपति शासन, 'सरकार' की तैयारी !

दिल्ली पहुंच गए एनडीए विधायक,जल्द बन सकती है नई सरकार

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के 20 से अधिक भाजपा विधायक पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इन विधायकों के साथ पार्टी की प्रदेश इकाई की अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी की मणिपुर इकाई की अध्यक्ष अधिकारीमयूम शारदा देवी ने इंफाल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी विधायकों को बुलाया गया है। हमें उम्मीद और विश्वास है कि जनता की सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा,चूंकि राजग सहयोगी दलों के सभी विधायकों को बैठक के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, इसलिए मुझे सकारात्मक

परिणाम की उम्मीद है। इससे पहले भाजपा के सभी विधायकों की बैठक हुई थी। राष्ट्रपति शासन की अवधि 12 फरवरी को समाप्त होने वाली है। सकारात्मक पहल की उम्मीद है। जब सिंह से पूछा गया कि

अगर वह सत्ता में होते तो क्या हालात अलग होते, इस पर उन्होंने कहा, सरकार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने मणिपुर में हालात बदलने की पूरी कोशिश की। पहाड़ी और घाटी दोनों इलाकों में काफी बदलाव हुए हैं। लामसांग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक एस राजन सिंह ने कहा, सरकार बनने की संभावना है। हालांकि, राज्य की स्थिति का जायजा लेने के बाद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नेता का चयन किया जाएगा। बैठक सोमवार शाम को होने की संभावना है। विधायक एच डिंगो ने बताया कि बैठक सोमवार शाम को है, लेकिन बैठक का एजेंडा अभी घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, हमें बस इतना बताया गया है कि आज ही दिल्ली पहुंच जाएं। खुराई निर्वाचन क्षेत्र के विधायक एल सुसिंद्रो ने कहा कि उन्हें दिल्ली बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।

शरद की सुबह

वही ताज है वही तख़्त है वही
जहर है वही जाम है
ये वही ख़ुदा की ज़मीन है ये
वही बुतों का निज़ाम है
बड़े शौक़ से मिरा घर जला कोई आँच तुझ
पे न आएगी
ये ज़बाँ किसी ने ख़रीद ली
ये क़लम किसी का ग़ुलाम है
यहाँ एक बच्चे के ख़ून से
जो लिखा हुआ है उसे पढ़ें
तिरा कीर्तन अभी पाप है
अभी मेरा सज्दा हराम है
मैं ये मानता हूँ मिरे दिए तिरी
आँधियों ने बुझा दिए
मगर एक जुगनू हवाओं में
अभी रौशनी का इमाम है
मिरे फ़िक्र-ओ-फ़न तिरी अंजुमन न
उरूज था न ज़वाल है
मिरे लब पे तेरा ही नाम था मिरे
लब पे तेरा ही नाम है

– बशीर बद्र

संसद में राहुल के 'चीन राग' पर भाजपा हुई आक्रामक

● रिजिजू बोले-स्पीकर का अपमान हुआ, कांग्रेस,पाप के लिए माफी मांगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कथित रूप से संसदीय नियमों की अनदेखी की। राहुल गांधी के चीन से जुड़े बयान को लेकर भाजपा ने सदन की मर्यादा तोड़ने और लोकसभा अध्यक्ष का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को सदन में नियमों के तहत बोलने की सख्त हिदायत दी। अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई सदस्य तथ्यों और संसदीय नियमों के दायरे में बात नहीं रखता

है, तो उन्हें दूसरे वक्ताओं को अवसर देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह चेतावनी उस वक्त दी गई जब राहुल गांधी ने चीन से जुड़े एक गैर-सूचीबद्ध मुद्दे को उठाने की कोशिश की।

राहुल गांधी देश से माफी मांगें: किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए सभी सांसद सदन में मौजूद थे और राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर बोलने का अवसर दिया गया था। लेकिन शुरुआत से ही उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और एक ऐसी किताब से उद्धरण देने लगे, जिसकी न तो प्रामाणिकता स्पष्ट थी और न ही उसके प्रकाशन की कोई जानकारी दी गई। उन्होंने कहा राहुल गांधी नियमों की अनदेखी करते हैं।

सदन नियमों से चलता है, मनमर्जी से नहीं

किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में चीन जैसे संवेदनशील मुद्दे को बिना सूचीबद्ध कराए उठाया और एक पत्रिका के लेख से उद्धरण देने की कोशिश की, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के फैसले का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी द्वारा चीन सीमा का मुद्दा उठाने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह बताए कि क्या वह 1959 और 1962 में चीन द्वारा कब्जाई गई जमीन को वापस ला सकती है। रिजिजू ने कहा कि चीन सीमा से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस के पाप भारी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव वडोदरा में महंत स्वामी महाराज के 92वें जन्मजयंती महोत्सव में हुए शामिल

गुजरात की धरा ने दिया है, मानव कल्याण और सनातन का संदेश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गुजरात की धरती भारत सहित अनेक राष्ट्रों में धर्म, आध्यात्म, सनातनी परम्परा, मानव कल्याण और सेवा मूल्यों को चेतना से जोड़ने का कार्य कर रही है। इस धरा से कभी महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसी विभूतियों ने राष्ट्र को योगदान

● जन्म उत्सव में एक साथ श्लोक पाठ का बना नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

● मध्यप्रदेश से जुड़ी हैं स्वामी जी की जीवन यात्रा की जड़ें

दिया, वहीं अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज सऊदी अरब सहित अबूधाबी और अमेरिका में स्वामी नारायण अक्षर धाम के पारम्परिक हिन्दू मंदिर और विश्व के अनेक देशों में 600 से अधिक मंदिरों का निर्माण उल्लेखनीय है। सत्संगदीक्षा जैसे शास्त्र सम्मत ग्रंथ की रचना और हजारों सेवाभावी नवयुवान संतों का निर्माण सनातन की परम्परा को ऊंचाइयां दे रहा है। यह गर्व की बात है कि महंत स्वामी महाराज की जीवन यात्रा की जड़ें मध्यप्रदेश से भी जुड़ी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को

संस्कृत श्लोकों के सामूहिक पाठ का बना नया रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महंत स्वामी महाराज के 92वें जन्मजयंती महोत्सव में 15 हजार 666 बच्चों को एक साथ स्वामी जी द्वारा रचित 'सत्संग दीक्षा' ग्रंथ के 315 श्लोकों का पाठ किए जाने को एक उपलब्धि बताया। इस गतिविधि का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री पटेल ने महंत स्वामी महाराज से जनकल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी जी ने दोनों मुख्यमंत्रियों का पुष्पमाला से अभिनंदन किया। कार्यक्रम में श्री गुणातितानंद स्वामी की अद्भुत महिमा एवं जीवन पर केंद्रित नाटक का मंचन किया गया। इसमें गौंड साम्राज्य के राजा श्री भगवत सिंह के चरित्र के माध्यम से गुणातितानंद स्वामी के सामाजिक और धार्मिक कार्यों की जानकारी दी गई।

गुजरात के वडोदरा में पूज्य महंत स्वामी महाराज की 92वीं जन्म वर्षगांठ पर उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वामी को जन्म दिवस की बधाई देते हुए उनके शतायु होने की कामना की और आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में स्वामी जी का जन्म शताब्दी समारोह अधिक भव्य रूप में आयोजित होगा। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वडोदरा एक नगर नहीं बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है जहां भक्ति के साथ सेवा की सुदीर्घ परम्परा है। इस धरती से गुरू के उस संदेश का प्रसार हो रहा है, जो भगवान स्वामी नारायण से लेकर पूज्य महंत स्वामीजी के जीवन में अभिव्यक्त होता है।

● अनिल चौहान का दौरा भारत से पाकिस्तान को डबल झटका

पहले पिनाका रॉकेट दिया, अब सीडीएस पहुंचे आर्मेनिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान एक उच्च स्तरीय प्रतिमंडल के साथ रविवार को आर्मेनिया पहुंचे हैं। उनकी चार दिनों की आर्मेनिया यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। भारत के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी की आर्मेनिया यात्रा उसे स्वदेशी गाइडेड पिनाका रॉकेट की पहली खेप भेजे जाने के फौरन बाद हो रही है। भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा संबंधों में यह नई गर्मजोशी पाकिस्तान और उसके मुस्लिम मित्र देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है और सीडीएस का वहां पहुंचना उसके लिए दोहरा बड़ा झटका है। सीडीएस अनिल चौहान की उच्च-स्तरीय प्रतिधिनिध मंडल के साथ येरेवान यात्रा को दोनों देशों के द्विपक्षीय सैन्य संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर की ओर से एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के लिए यह दौरा साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने और लंबे समय तक चलने वाले रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।

आर्मेनिया को भेजी है गाइडेड पिनाका रॉकेट– सीडीएस अनिल चौहान के इस चार दिवसीय दौरे की अहमियत का अंदाजा इसी से लगता है कि उनके स्वागत के लिए येरेवान में आर्मेनिया में भारत के राजदूत निलाक्षी साहा सिन्हा के साथ आर्मेनियाई सशस्त्र सेना के डिप्टी चीफ मेजर जनरल तैमूर शाहनजार्यन भी मौजूद थे। यह नहीं भूलना चाहिए कि दो हफ्ते पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मेनिया के लिए भारत में बनी गाइडेड पिनाका रॉकेट की पहली खेप रवाना की है। इस रॉकेट को पुणे स्थित सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है। 2022 के सितंबर में आर्मेनिया ने भारत से चार पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये की डील की थी। **पिनाका रॉकेट का पहला अंतरराष्ट्रीय खरीदार–** आर्मेनिया डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर का पहला अंतरराष्टीय खरीदार भी है। भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने की कोशिशों में जुटा है, बल्कि ग्लोबल लीडर बनने की ख्वाहिश रखता है और आर्मेनिया के साथ इसकी डिफेंस डील ने इसपर गहरी छाप छोड़ी है।

आर्मेनिया में पाकिस्तानी इरादों को डबल झटका

भारत के लिए आर्मेनिया के साथ रणनीतिक साझेदारी की अहमियत इसलिए रही है, क्योंकि यह रूस, तुर्की और ईरान की सीमा से सटा है। दूसरी तरफ आर्मेनिया और पाकिस्तान में पहले राजनयिक संबंध नहीं थे। पिछले साल सितंबर में ही दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध बहाल करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। इससे पहले पाकिस्तान आर्मेनिया से इसलिए दूरी बनाए था, क्योंकि एक और मुस्लिम देश अजरबैजान की आर्मेनिया से नहीं बनती थी। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने नजदीकी सहयोगी तुर्की के साथ अजरबैजान ने भी भारत के खिलाफ अपना असली मंसूबा जाहिर कर दिया था। ऐसे में आर्मेनिया में भारत की नए सिरे से रणनीतिक पहुंच पाकिस्तान के लिए डबल झटका है। पहले उसके मित्र अजरबैजान के पुराने दुश्मन को गाइडेड पिनाका रॉकेट मिला, अब सीडीएस ने वहां पहुंचकर भारत के साथ उसकी नजदीकी बयां कर दी।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20°c न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 03 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

दर्द में डूबी सुनेत्रा पवार दुख बांटने पहुंचीं सतारा

● वडेट्टीवार बोले-80 फीसदी लोग मान रहे कुछ गड़बड़ है

पुणे/मुंबई (एजेंसी)। राजनीति में खुद (स्व) से बड़ा संगठन होता है, शायद यही वजह है कि अजित पवार की मौत के चौथे दिन डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करने के बाद सुनेत्रा पवार सबसे पहले सतारा पहुंचीं।

उन्होंने यहां पर महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें नमन किया। इसके बाद सीधे अजित पवार को पीएसओ (पर्सनल सिक्योरिटी ऑफीसर) विदिप जाधव के घर पहुंचीं। खुद दुख में और दर्द में डूबीं सुनेत्रा पवार ने जाधव की पत्नी का हाथ थामकर सांत्वना दी, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अजित पवार के प्लेन क्रैश पर राजनीति गरमाती जा रही है। एनसीपी नेता अमोल मिटकरी के सवालों के बाद संजय राउत ने सवाल उठाए थे, अब कांग्रेस

नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि 80 फीसदी लोगों का मानना है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। वडेट्टीवार ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में गंदगी फैल चुकी है। सुनेत्रा पवार ने अजित दादा के अंगरक्षक विदिप जाधव के परिवार से मुलाकात के दौरान कहा कि मैं किसी भी मुश्किल में आपके साथ हूं। महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत विदीप जाधव 2009 में भर्ती हु थे। सुनेत्रा उनके तरडगांव (तहसील फलटन) स्थित घर पर पहुंचीं। सुनेत्रा पवार ने विदीप जाधव की पत्नी और बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि मैं किसी भी मुश्किल में आपके साथ हूं।

यह मंजर देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सुनेत्रा ने परिवार के सदस्यों के कामकाज और नौकरी के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि सीआईडी जांच से कुछ हल नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 80 फीसदी लोगों का मानना है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। पूछा कि आखिरी समय पर पायलट क्यों बदला गया।

सूरत में सैफ को लव-जिहादी बताकर काले झंडे दिखाए

● इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में पहुंचे थे, हिंदू संगठनों ने किया विरोध

सूरत (एजेंसी)। गुजरात के सूरत में सोमवार की रात हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने लव जिहादी का नारा लगाते हुए सैफ अली खान को काले झंडे दिखाए। दरअसल सैफ यहां हो रही इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के लिए पत्नी करीना कपूर और बेटों के साथ सूरत पहुंचे थे।

अपनी टीम का मैच खत्म होने के बाद वे परिवार के साथ स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारी युवाओं ने हाथों में काले झंडे लहराते हुए उनका विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने लव जिहादी है के नारे लगाए। हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस बल ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में कर सैफ अली खान के काफिले को सुरक्षित वहां से निकालकर होटल तक पहुंचा दिया। इस घटना के वीडियो वायरल हो

रहे हैं। सूरत में 9 फरवरी तक होनी है सूरत में 9 जनवरी से इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है। सूरत के लालभाई कॉन्ट्रेक्टर स्टेडियम में लीग के 44 मैच खेले जाएंगे।

अशोकनगर, आगर-मालवा, टीकमगढ़ में बारिश

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आंधी, ओले और बारिश वाला मौसम है। सोमवार सुबह अशोकनगर, आगर-मालवा, टीकमगढ़ में बारिश हुई। वहीं, कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। हालांकि, ठंड का असर कम है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर ही चल रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। इससे पहले दतिया, ग्वालियर, नर्मदापुरम, उज्जैन, खजुराहो, रीवा, सतना, भोपाल, गुना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, श्योपुर, जबलपुर, दमोह, मंडला, नरसिंहपुर, नौगांव, मलाजखंड, टीकमगढ़ समेत कई जिलों में कोहरे का असर भी देखा गया।

राज्यसभा में उठा इंदौर में दूषित-पानी से मौत का मामला

कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा– सरकार लोगों को जहरीला पानी पिला रही है

भोपाल (नप्र)। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 29 से अधिक मौतों का मामला राज्यसभा में गूंजा है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने सदन में इस मामले को उठाते हुए कहा है कि पानी सबसे गंभीर विषय है और जहरीला पानी सरकार पिला रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

तिवारी ने कहा कि इस विभाग में जितना करप्शन है, शायद किसी और विभाग में उतना करप्शन नहीं है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इसकी कार्ययोजना से अवगत कराएं।

सोमवार को राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में कांग्रेस से राजस्थान से सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है। मानवता से जुड़ा है। हिन्दुस्तान के हर आदमी से जुड़ा सवाल है। इसलिए सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। मंत्री भी गुजरात से हैं। गांधी नगर गुजरात में प्रदूषित जल पीकर कितने लोग बीमार हुए।

इंदौर में कितने लोग मरे, 29 लोग मरे हैं, यह हालिया स्थिति है। राज्य मंत्री तो लड़खड़ा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री उठिए, मोर्चा संभालिए।

मैं जानना चाहता हूं कि विश्व की मानवता से जुड़ा हुआ, हर इंसान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सदन को आश्वस्त करेंगे कि जो ग्राउंड वाटर है, उसकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए क्या कार्ययोजना आपके पास है।

इमरान प्रतापगढ़ी ने पूछे सवाल- क्या केंद्र ने राज्य से सवाल किया, रिपोर्ट मांगी– राज्यसभा में महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए वे विभागीय मंत्री से पूछना चाहते हैं कि इन मौतों का जिम्मेदार किसको माना जा रहा है?

क्या इसमें सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? क्या जल शक्ति मंत्रालय ने इसमें संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से सवाल किया? क्या इस मामले में राज्य सरकार ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की? इसकी जानकारी दी जाए।

सांसद डॉ. सैयद नासिर हुसैन ने भी सवाल पूछे थे– इससे पहले कर्नाटक से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता डॉ. सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में इंदौर के स्वच्छता और जल आपूर्ति सिस्टम को लेकर सरकार से सीधे सवाल पूछे थे।

इंदौर में दूषित पानी से अब 32 लोगों की मौत– गौरतलब है कि इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मौतों का सिलसिला जारी है। आज भी एक व्यक्ति की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई है। इंदौर में दूषित पानी से मौत का आंकड़ा अब 32 तक पहुंच गया है।

बंग भवन के पास दिल्ली पुलिस से भिड़ गईं ममता

एसआईआर पीड़ितों के प्रति 'संवेदनशीलता' की मांग

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दिल्ली के बंगा भवन के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों का सामना किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में किसी आंदोलन के लिए नहीं आई हैं। उनका मकसद चुनावी सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाना है। ममता बनर्जी रविवार को दिल्ली पहुंची थीं। इसके बाद वो बंगा भवन गईं, जो दिल्ली में पश्चिम बंगाल सरकार का गेस्ट हाउस है। वहां वे परिवार ठहरे हुए हैं जो बंगाल में चुनावी सूची की जांच प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं। इमारत के बाहर भारी पुलिस बल तैनात देखकर मुख्यमंत्री नाराज हो गईं। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से कहा कि वे बंगाल के लोगों के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगा भवन में बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से कहा, हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमारी चुनाव आयोग के साथ बैठक तय है। लोग परेशान हैं, क्या उनके परिवार मीडिया से बात भी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां भी एसआईआर से प्रभावित परिवार ठहरे हैं, वहां दिल्ली पुलिस तैनात है। जब दिल्ली में धमाका होता है तो दिल्ली पुलिस कहां होती है। मुख्यमंत्री ने कहा मैं दिल्ली पुलिस को दोष नहीं देती, मैं उन लोगों को दोष देती हूं जो शीर्ष पर हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग देश की रक्षा करने में नाकाम हैं और आम लोगों पर एसआईआर के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं।

एक-एक कार्यकर्ता को गढ़ना और उनका ध्यान रखना, शरद जी की कुशलता थी

भोपाल। शाखा लगाने के लिए कितना परिश्रम लगता है और सतत प्रक्रिया अपनानी होती है, यह शरद जी ने अपने व्यवहार से कार्यकर्ताओं को सिखाया। संघ की शाखाएं बढ़ें लेकिन उनकी गुणवत्ता भी बढ़े, शरद जी का हमेशा यह प्रयास रहता था। वे संघकार्य के कुशल शिल्पी थे। एक-एक कार्यकर्ता को गढ़ना और उनका ध्यान रखना, शरद जी की कुशलता थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख अरुण जैन ने यह विचार 'शरद स्मृति व्याख्यान' में व्यक्त किए। कार्यक्रम का आयोजन अर्चना प्रकाशन की ओर से अपने संस्थापक स्वर्गीय शरदचंद्र मेहरोत्रा की पुण्यतिथि के प्रसंग पर मानस भवन, भोपाल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्यभारत प्रान्त के संघचालक अशोक पांडेय ने की। इस अवसर पर मंच पर अर्चना प्रकाशन न्यास के अध्यक्ष लाजपत आहूजा भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर अरुण जैन ने कहा कि जब मध्यभारत में शरद जी प्रचारक होकर आये तो संघकार्य को नया आयाम मिला। उनके प्रयासों से शिवपुरी और ग्वालियर में आवासीय विद्यालय शुरू हुए। गोविंदनगर में शिक्षा और सेवा का जो

प्रकल्प आज दिखाई दे रहा है, उसकी नींव में शरद जी थे। वे धुन के पक्के थे, जिस काम की ठान लेते, उसे करके ही मानते थे। वे बहुत व्यवहारिक थे। धरातल पर कार्य करने के अभ्यासी थी। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रान्त के संघचालक अशोक पांडेय ने कहा कि किसी भी महापुरुष को याद करके हम अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं करते हैं। वे दीपस्तंभ हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं। शरद जी अपने अंतिम समय तक देश-समाज की चिंता करते रहे। अपने ध्येय के लिए पूर्ण समर्पित शरद जी का जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय है। कार्यक्रम के प्रारंभ में अर्चना प्रकाशन के निदेशक ओमप्रकाश गुप्ता ने प्रकाशन की स्थापना की पृष्ठभूमि एवं वर्तमान गतिविधियों की जानकारी दी। आभार ज्ञापन अरुण उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम के दौरान अर्चना प्रकाशन न्यास की वार्षिक स्मारिका 'शताब्दी के निहितार्थ' का लोकार्पण किया गया, जिसका संपादन प्रो. उमेश कुमार सिंह ने किया है। इसके साथ ही डॉ. विकास दवे की 'भारत का जय घोष - वंदे मातरम्', लाजपत आहूजा की 'धर्म की ढाल - गुरु गोविंद बहादुर' तथा रमेश शर्मा की 'भगवान बिरसा मुंडा' पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

रेयर अर्थ के लिए

अमेरिका करेगा 'महागठबंधन'

● भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत जुटेंगे 20 दिग्गज देश, चीन की उड़ी नींद

वॉशिंगटन (एजेंसी)। भारत के विदेश मंत्री अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल्स पर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। अमेरिका के नेतृत्व में दुर्लभ खनिजों से चीन के वर्चस्व को मिटाने के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसमें भारत शामिल होगा। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने पिछले महीने नई दिल्ली में कहा था कि फरवरी में भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। अमेरिका में ये बैठक स्थानीय समय के मुताबिक 2-4 फरवरी तक होने वाली है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में 2 फरवरी को जारी एक बयान में कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से बुलाई गई क्रिटिकल

मिनरल्स मिनिस्टीरियल में हिस्सा लेंगे। वॉशिंगटन में होने वाली बैठक में अमेरिका के अलावा भारत, यूरोपीय यूनियन, यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हो रहे हैं।

● **पैक्स सिलिका के जरिए ट्रंप सुधार पाएंगे सहयोगियों से संबंध–** पैक्स सिलिका की बैठक में वो देश शामिल हो रहे हैं, जिनके अमेरिका से रणनीतिक और सहयोगी संबंध रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने करीब करीब सभी के साथ अमेरिका के संबंध खराब कर लिए हैं। ऐसे में पैक्स सिलिका सम्मेलन को ट्रांसअटलांटिक संबंधों को सुधारने और चीन से जोखिम कम करने के लिए रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें खास तौर पर स्टील पर केंद्रित एक गठबंधन भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को कहा है कि वह 1.2 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की लागत से मिनरल्स को लेकर एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाएगा, ताकि चीन से होने वाली सप्लाई चेन की रुकावट के असर को कम किया जा सके।

● पाकिस्तानी नेता बोले-हमारा जीरो-टैरिफ हनीमून खत्म, अरबों डॉलर के नुकसान का खतरा

भारत-ईयू डील से

पाक में 1 करोड़ नौकरियां खतरे में

इस्लामाबाद (एजेंसी)। भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) से पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। उसे अरबों डॉलर के नुकसान का भी डर है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस समझौते को लेकर गुरुवार को कहा कि वह ईयू के अधिकारियों के संपर्क में है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि भारत-ईयू का उसके निर्यात पर क्या असर पड़ेगा। वहीं, पाकिस्तान के

पूर्व वाणिज्य मंत्री गोहर एजाज ने सोशल मीडिया पर लिखा-ईयू के साथ पाकिस्तान का जीरो-टैरिफ हनीमून खत्म हो गया है और करीब एक करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। सरकार उद्योगों को सस्ती बिजली, कम टैक्स और आसान कर्ज दे, ताकि वे दूसरे देशों की इंडस्ट्री से मुकाबला कर सकें।

● **यूरोपीय मार्केट में पाकिस्तान की बढ़त खत्म होने का खतरा–** पाकिस्तान इस डील से परेशान इसलिए है क्योंकि लंबे समय से उसे यूरोपीय मार्केट में भारत पर बढ़त हासिल थी। इसकी वजह ईयू की प्लस योजना थी। इस योजना के तहत पाकिस्तान को अपने करीब 66 फीसदी उत्पादों को बिना टैक्स के यूरोप भेजने की सुविधा मिली हुई थी। इसमें कपड़ा और रेडीमेड कपड़े जैसे सामान शामिल थे। वहीं भारत को ऐसे ही सामान पर 9 से 12 फीसदी तक टैक्स देना पड़ता था। इसके बावजूद पाकिस्तान का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 6.2 अरब डॉलर रहा, जबकि भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 5.6 अरब डॉलर का था। अब भारत और ईयू के बीच हुआ यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है।

शहडोल में करंट से बाघों की मौत पर जवाब मांगा

एक्टिविस्ट बोले, 33 दिनों में एमपी में 11 बाघों की मौत सुरक्षा पर गंभीर सवाल

भोपाल (नप्र)। शहडोल में करंट से दो बाघों की मौत के मामले में राज्य सरकार ने शहडोल के सीसीएफ से जवाब तलब किया है। मामले में लापरवाह वन अफसरों पर कार्रवाई के लिए कहा है। चीफ वाइल्डलाइफ शुभ रंजन सेन ने इस मामले में जांच रिपोर्ट मांगे जाने की पुष्टि की है। दूसरी ओर बाघों की लगातार हो रही मौत के मामले में वाइल्डलाइफ चीफ को हटाने की मांग की जाने लगी है। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि 2026 में 33 दिनों में 11 बाघों की मौत हो चुकी है।

वन विभाग को रविवार रात सर्किल मसिरा के आरएफ 382 क्षेत्र के पास एक

बाघ का शव मिलने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान सोमवार तड़के उसी क्षेत्र में एक बाघिन का शव भी बरामद हुआ। दोनों शव राजस्व क्षेत्र में एक-दूसरे के नजदीक पाए गए, जिससे यह पुष्टि हुई कि उनकी मौत एक ही घटना में हुई है। मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर दोनों बाघों की मौत बिजली के करंट से होने की पुष्टि हुई है। जांच में यह सामने आया है कि एक किसान ने अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत में अवैध रूप से बिजली का तार बिछाया था। इसी तार की चपेट में आने से दोनों बाघों की जान चली गई।

बाघों की गणना चल रही और बाघ मर रहे

वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे का कहना है कि प्रदेश में इस समय बाघों की गणना का काम चल रहा है। 2025 से यह काम शुरू हुआ है जो 2026 में मई तक चलने वाला है। ऐसे में टाइगर एरिया में कैमरे इंस्टाल किए जा रहे हैं और बाघों की मौत हो रही है। इससे सवाल उठता है कि वन विभाग के लोग क्या कर रहे हैं? दुबे ने कहा कि एमपी में 2025 में 55 बाघों की मौत हुई थी। वर्ष 2026 में 33 दिनों के अंतराल में आज हुई बाघों की मौत को मिलाकर 21 बाघ-बाघिन की मृत्यु हुई है, इसमें से 11 एमपी में मृत हुए हैं जो बाघों की सुरक्षा पर सवाल है।

एसडीओ, रेंजर, फारेस्टर को सस्पेंड किया जाए

आरटीआई एक्टिविस्ट वाइल्डलाइफ अजय दुबे का कहना है कि एमपी में बाघों के मामले में जिस तरह से लापरवाही की जा रही है, वह गंभीर और चिंतनीय है। खासतौर पर शहडोल संभाग में भारी लापरवाही हो रही है। बाघों के शिकार पर शहडोल के सीसीएफ से पीसीसीएफ (हॉफ) द्वारा जवाब-तलब कर लापरवाह वन अफसरों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन स्थिति पर नियंत्रण के लिए रेंजर, एसडीओ, फॉरेस्टर को सस्पेंड किया जाना चाहिए।

दुबे का कहना है कि बिजली के करंट से एक नर और एक मादा बाघ की मौत हो गई है। मृत बाघिन के शावक लापता हैं। यह लगातार लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश के वन्यजीव विभाग में जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। दुबे ने कहा कि हम वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ता वाइल्डलाइफ चीफ शुभ रंजन सेन को तत्काल हटाने की मांग करते हैं।

मंत्रालय में राष्ट्र-गीत 'वंदे-मातरम्' एवं राष्ट्र-गान 'जन-गण-मन' का सामूहिक गायन हुआ

भोपाल (नप्र)। मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में फरवरी माह के प्रथम शासकीय कार्य दिवस पर सोमवार को राष्ट्र-गीत 'वंदे-मातरम्' एवं राष्ट्र-गान 'जन-गण-मन' का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने मधुर धुनें प्रस्तुत की। सामूहिक गायन में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर शामिल हुई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, श्री मनु श्रीवास्तव, श्री संजय कुमार शुक्ला, सचिव श्री एम. रघुराज, सहित मंत्रालय वल्लभ भवन, सतपुड़ा-विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी एवं पुलिस अधिकारी आदि उपस्थित थे।

समाधान योजना में 852 करोड़ 76 लाख मूल राशि हुई जमा : ऊर्जा मंत्री

भोपाल (नप्र)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण में 852 करोड़ 76 लाख रूपये मूल राशि जमा हुई है। साथ ही 350 करोड़ 67 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है। योजना में 17 लाख 15 हजार उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। पिछले साल 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों बकायादार उपभोक्ताओं ने सौ फीसदी तक छूट का लाभ लिया। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि तीन माह से अधिक के शेष बकायादार उपभोक्ता योजना के द्वितीय चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा कर 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठायें। द्वितीय चरण 28 फरवरी तक चलेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 5 लाख 27 हजार बकायादार उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराकर लाभ लिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 534 करोड़ 16 लाख की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 263 करोड़ 94 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है। इसी तरह पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 6 लाख 8 हजार उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। मूल राशि 174 करोड़ 94 लाख रूपये जमा हुई है तथा 62 करोड़ 11 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रान्तर्गत 5 लाख 80 हजार उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। कुल मूल राशि 143 करोड़ 66 लाख रूपये जमा हुई है। साथ ही 24 करोड़ 62 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है।

कर्मचारी मामलों को आंतरिक मैकेनिज्म के जरिए सुलझाएं : हाईकोर्ट

भोपाल। उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालयों में सर्विस मैटर से संबंधित मामलों में बेतहाशा वृद्धि पर चिंता जताते हुए इन मामलों के निराकरण हेतु आंतरिक मैकेनिज़्म स्थापित करने का परामर्श दिया है। इस समय सर्विस मैटर से संबंधित लगभग 50 हजार मामले लंबित हैं। इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भेजे जाने के निर्देश भी दिए हैं। आम कर्मचारियों को हर छोटे-बड़े न्यायसंगत काम के लिए भी न्यायालय जाना पड़ता है। हजारों मामले ऐसे भी हैं जिनमें न्यायालय का निर्णय आ चुका है परंतु कर्मचारी न्यायालयीन निर्णय का पालन कराने के लिए भटक रहे हैं। इस स्थिति में सुधार हेतु न्यायालय पहले भी समय-समय पर सचेत करता रहा है। सुशीला देवी प्रकरण में माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि यदि किसी एक मामले में न्यायालयीन फैसला हो जाये तो उसे उस जैसे सभी मामलों में लागू माना चाहिए। मंत्रालय सेवा अधिकारी/कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि 1995-96 में राज्य कर्मचारी कल्याण समिति गठित की गयी थी लेकिन उसे कोई अधिकार न होने के कारण उसके कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले। वर्ष 2007 से 2013 तक कर्मचारी मामलों का प्रभारी मंत्री नामांकित करने की एक अभिनव व्यवस्था विकसित की गयी थी। उसके अच्छे परिणाम आये थे लेकिन फिर वह व्यवस्था बंद हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रशासनिक न्यायाधिकरण पुनः स्थापित करना चाहिए।

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, योजनाओं का करें प्रभावी पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, अधोसंरचना विकास, चिकित्सकीय मैनपावर की उपलब्धता एवं चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के लिए सभी योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अधोसंरचना विकास, चिकित्सकीय सहायक एवं चिकित्सकीय मैनपावर की नियुक्ति तथा स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन से संबंधित प्रस्तावों की गहन समीक्षा की। उन्होंने इन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। रिमोट लोकेशन में स्थित मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त इंसेंटिव प्रदान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट अनुमोदन हेतु शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में योग्य शिक्षण स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित

करना गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय शिक्षा के लिए अहम है। बैठक में अंतर्विभागीय विषयों पर चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर औपचारिकताओं की पूर्ति प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो। सीएम केयर्स के अंतर्गत टर्शरी केयर स्वास्थ्य सुविधाओं में अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता के साथ-साथ आवश्यक मैनपावर की नियुक्ति के प्रस्तावों को प्राथमिकता से अग्रेषित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर रोगों के उपचार हेतु टर्शरी केयर सेवाओं को और अधिक मजबूत किया जाना आवश्यक है, ताकि नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदेश के हर क्षेत्र में उपलब्ध हों।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने दमोह, छतरपुर एवं बुधनी मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए आवश्यक शिक्षण स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र में संचालन शुरू करने के लिए प्राथमिकता से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति की जाये। बैठक में केंद्रीय बजट के प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने उपलब्ध बजटीय संसाधनों के समयबद्ध एवं प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विभाग को ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त श्री धनराज एस, एमडी एमपीपीएचएससीएल श्री मयंक अग्रवाल, एमडी एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अरुणा कुमार सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

वाहन रैली और कृषि रथ के माध्यम से किसानों को किया जा रहा है जागरूक

भोपाल (नप्र)। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में वाहन रैली के माध्यम से किसानों को खेती की नवीन तकनीकों को अपनाकर फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूक किया गया। इसके तहत विभिन्न जिलों में वाहन रैली आयोजित की गई।

धार जिला मुख्यालय पर विधायक श्रीमती नीना वर्मा एवं कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा द्वारा हरी झण्डी दिखाकर किसान जागरूकता वाहन रैली को रवाना किया गया। जिले में किसानों के लिए कृषि एवं कृषि से संबंधित विभागों की योजनाओं का प्रचार-प्रसार कृषि रथ के माध्यम से निरंतर प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जा रहा है।

कृषक कल्याण वर्ष के प्रचार-प्रसार के लिए कृषि रथ के मुख्य आधार स्तंभ- जैविक खेती एवं प्राकृतिक कृषि क्षेत्रों का विस्तार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रचार-प्रसार, एकीकृत पोषक तत्व, कीट एवं रोग प्रबंधन, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, विभागीय कृषि योजनाओं का प्रचार-प्रसार, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, ई-विकास प्रणाली अंतर्गत ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था, पराली प्रबंधन आदि विभागीय योजनाओं से जागरूक किया जा रहा है।

सिवनी जिला मुख्यालय पर किसानों को जागरूक करने के लिए मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य किसानों में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें शासन की विभिन्न कृषक हितैषी योजनाओं से जोड़ना रहा। मोटरसाइकिल रैली में सिवनी विधायक श्री दिनेश राय ने स्वयं मोटरसाइकिल चलाकर सहभागिता की और किसानों का उत्साहवर्धन किया।

बैतूल जिले में किसानों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर अधिकारियों ने किसानों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, नवाचारों और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने का संदेश दिया। रैली में मोटरसाइकिल, चार पहिया वाहन एवं विभागीय वाहनों के माध्यम से आकर्षक बैनर-पोस्टर लगाकर किसान कल्याण से जुड़े संदेश प्रसारित किए गए। इसी तरह पांढुर्णा जिले में भी किसान मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया।

नर्मदा परिक्रमा पथ के आश्रय स्थलों पर होगा व्यापक वृक्षारोपण : मंत्री पटेल

राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक सम्पन्न

भोपाल (नप्र)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने नर्मदा परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आश्रय स्थलों पर व्यापक वृक्षारोपण करने के निर्देश दिये है। श्री पटेल सोमवार को जीवनदायिनी माँ नर्मदा के जल को निर्मल बनाए रखने, उनके प्रवाह को अविरल सुनिश्चित करने तथा नर्मदा से जुड़े समग्र विकास कार्यों के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में

सर्वश्री छोटे सिंह, दिनेश जैन, श्रीमती हर्षिका सिंह, श्री अविप्रसाद एवं श्री दीपक आर्य उपस्थित थे। मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों को परिक्रमा पथ पर प्रस्तावित पुल, पुलिया एवं ब्रिज के सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण कर सुनियोजित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये।

बैठक में विधानसभा से संबंधित लंबित प्रकरणों की विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। मंत्री श्री पटेल ने सभी लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जनहित से जुड़े विषयों का शीघ्र समाधान हो सके। बैठक में माँ नर्मदा के संरक्षण एवं विकास को जनभागीदारी से जोड़ने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया।

सतना के रामवन मंदिर परिसर में आपत्तिजनक वीडियो

सतना (नप्र)। सतना जिले के रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र के रामवन स्थित मंदिर परिसर से जुड़ा एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में एक युवक और युवती को मंदिर प्रांगण में स्थापित मूर्ति के ठीक पीछे आपत्तिजनक स्थिति में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया था, जो बाद में तेजी से फैल गया।

मामले के सामने आने के बाद मंदिर के पुजारी अंश शर्मा (पिता रामायण शर्मा) ने सोमवार को रामवन चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुजारी ने अपनी शिकायत में कहा कि मंदिर परिसर जैसी आस्था से जुड़ी जगह पर इस तरह की हरकत से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और क्षेत्र की मर्यादा भंग हुई है।

वीडियो रिकॉर्ड करने वाले को भी ढूंढ रही पुलिस- शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात युवक-युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है

कि वीडियो की सत्यता और उसके समय की पुष्टि की जा रही है। साथ ही, वीडियो बनाने और उसे वायरल करने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचा जा सके।

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी साझा न करें। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बजरंग दल ने नाराजगी व्यक्त की- उधर, बजरंग दल के प्रांत गौशाला प्रमुख सचिन शुक्ला ने भी इस वीडियो पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि वायरल वीडियो के आधार पर युवक-युवती की पहचान कर वैधानिक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में धार्मिक स्थलों पर ऐसी आपत्तिजनक घटनाएं न हों।

एसआई का आरोप- ग्रामीण एसपी ने गालियां दीं...झूठी जांच शुरू कराई

ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकालने की धमकी दी; लिखा- शिकायत को ही सुसाइड नोट मानें

भोपाल (नप्र)। भोपाल के देहात एसपी रामशरण प्रजापति पर एक सब इंस्पेक्टर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सूखी सेवनिया थाने के एसआई केसी यादव ने कहा है कि एसपी ऑफिस में उन्हें गालियां दी गईं। विरोध करने पर धक्के देकर बाहर करने की धमकी मिली।

थाने आने के बाद एसआई यादव ने रोजनामचा रिपोर्ट डाल दी। इसकी भनक एसपी प्रजापति को लग गई। उन्होंने दोबारा फोन पर फटकार लगाई। दो अलग-अलग प्रकरण में विभागीय जांच शुरू करा दी गई। एसआई केसी यादव ने सीनियर अफसरों से लिखित शिकायत की है। उन्होंने लिखा है कि यदि न्याय नहीं मिला तो शिकायत को ही सुसाइड नोट मान लिया जाए। एसआई यादव ने एसपी रामशरण प्रजापति की लिखित शिकायत की है।

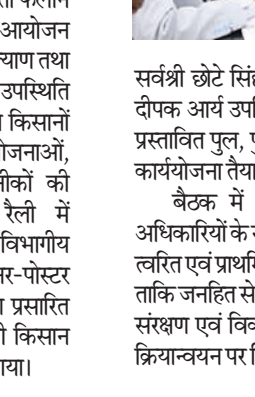

आईजी से लेकर मानवाधिकार आयोग तक को भेजी शिकायत- एसआई केसी यादव ने आईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री और मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी है। इसमें अपने साथ हुई बदसलूकी का जिक्र करते हुए लिखा- 14 सितंबर 2025 को एसपी रामशरण प्रजापति ने आबकारी एक्ट के एक अपराध की डायरी मंगाई थी। मीटिंग के बाद मैंने हाईकोर्ट में भेजने के लिए डायरी वापस मांगी तो एसपी ने इसे गुस्ताखी मानकर अपशब्द कहे और डायरी एसडीओपी मंजू चौहान से लेने के लिए कह दिया।

30 साल की नौकरी में मेरे साथ पहली बार इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। मैंने व्यथित होकर आत्महत्या का मन बना लिया था, लेकिन स्टाफ के समझाने और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण इरादा बदल दिया। फिर मैंने थाने के रोजनामचे में पूरी घटना दर्ज कर दी।

लिखा- एसपी से महिला अधिकारी भी परेशान- एसआई यादव ने अपनी शिकायत में कई छोटे अफसरों को एसपी प्रजापति की प्रताड़ना का शिकार बताया है। उन्होंने लिखा- महिला अधिकारी भी परेशान हैं, लेकिन डर के कारण कोई सामने नहीं आ रहा है।

दो महीने पहले टीआई से हुआ था विवाद

यह पहला मामला नहीं है, जब एसपी देहात रामशरण प्रजापति का नाम विवादों में आया हो। पिछले साल नवंबर में भोपाल देहात क्षेत्र में पदस्थ थाना प्रभारी आशीष सप्रे को लाइन अटैच करने का आदेश उन्होंने जारी किया था। आदेश में टीआई को तत्काल प्रभाव से लाइन में आमद देने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, 24 घंटे के भीतर ही यह आदेश निरस्त कर दिया गया। टीआई को लाइन अटैच करने की कार्रवाई पशु मेले को शिफ्ट कराने की धमकी देने और व्यापारियों से बदसलूकी के आरोपों के बाद की गई थी।

लाइन अटैच किए जाने की सूचना मिलते ही टीआई आशीष सप्रे ने आपत्ति जताते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी सफाई दी, लेकिन एसपी ने उनका पक्ष स्वीकार नहीं किया और आदेश पर कायम रहे। इस दौरान टीआई और एसपी के बीच तीखी नोक-झोंक होने की भी चर्चा रही।

कुछ ही घंटों में निरस्त किया लाइन अटैच का आदेश

थाना प्रभारी आशीष सप्रे को लाइन अटैच करने के मामले में अप्रत्याशित रूप से कुछ ही घंटे बाद एसपी कार्यालय से एक और आदेश जारी हुआ था। इसमें लाइन अटैच करने का आदेश निरस्त कर दिया गया। एसपी रामशरण प्रजापति ने इस फैसले को पूरी तरह प्रशासनिक दृष्टि से लिया गया फैसला बताया था। तब से टीआई सप्रे अपने पद पर यथावत हैं।

दरअसल, टीआई को लाइन हाजिर करने का आदेश सामने आने के बाद कई हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया था। संगठनों ने चेतावनी दी थी कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो प्रदर्शन किया जाएगा।

एसआई के आरोपों पर एसपी ने नहीं दिया कोई जवाब

मीडिया ने एसआई केसी यादव की शिकायत पर एसपी रामशरण प्रजापति से पक्ष जानना चाहा, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। एसपी को मैसेज भेजा गया, लेकिन उसका भी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

बंदूक चलाने से लेकर जूडो-कराते तक की देंगे ट्रेनिंग

लव-जिहाद रोकने वार्डवार महिला नेटवर्क तैयार करेगी हिंदू उत्सव समिति

भोपाल (नप्र)। हिंदू उत्सव समिति ने लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से वार्ड और मोहल्ला स्तर पर महिला सदस्यों का संगठित नेटवर्क तैयार करने की विस्तृत रणनीति बनाई है। समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि संगठन अब केवल पर्व-त्योहारों तक सीमित भूमिका में नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक स्तर पर निरंतर और जमीनी हस्तक्षेप करेगा। उनका कहना है कि उत्सव तभी सार्थक है, जब समाज और परिवार सुरक्षित व खुशहाल हों।

तिवारी के अनुसार समिति हर वार्ड और मोहल्ले में युवक-युवतियों की संयुक्त टीमें बनाएगी। इन टीमों में महिलाएं केंद्रीय भूमिका में होगी। महिला सदस्य घर-घर जाकर माताओं, बहनों और युवतियों से संवाद करेंगी और उन्हें सतर्कता व जागरूकता के बिंदुओं पर समझाइश देंगी। समिति का तर्क है कि महिलाओं से जुड़े संवेदनशील विषयों पर महिलाओं की बात अधिक प्रभावी होती है, इसलिए अभियान की कमान मातृशक्ति को सौंपी जा रही है।

घर-घर संपर्क, मोहल्ला स्तर पर टीम मॉडल- समिति ने अभियान के लिए क्षेत्र-आधारित टीम मॉडल तैयार किया है। अध्यक्ष के मुताबिक वार्ड का

दायरा बड़ा होने के कारण हर मोहल्ले या बस्ती के हिसाब से अलग-अलग टीमें गठित की जाएंगी। उदाहरण के तौर पर पटेल नगर बस्ती में करीब 2000 परिवार हैं। यहां पांच टीमें बनाई जाएंगी, जो अपने-अपने क्षेत्र में नियमित संपर्क कर परिवारों से संवाद करेंगी। हर टीम में युवक और युवतियां मिलकर काम करेंगे, ताकि संवाद संतुलित और प्रभावी रहे।

महिला सदस्यता पर विशेष जोर

हिंदू उत्सव समिति ने एक वर्ष में एक लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसमें 35 से 40 फीसदी सदस्य महिलाएं और 18 वर्ष से अधिक आयु की युवतियां होंगी। तिवारी ने बताया कि संगठन के आंतरिक चुनाव और मतदान प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए वयस्क सदस्यों को ही जोड़ा जाएगा। माताओं, बहनों और युवतियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग-अलग स्तर पर संवाद और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

आत्मरक्षा की ट्रेनिंग : जूडो-कराते से हथियार संचालन तक

समिति की रणनीति का अहम हिस्सा आत्मरक्षा प्रशिक्षण है। अध्यक्ष के मुताबिक फिलहाल संगठनात्मक ढांचा और टीमों का गठन किया जा रहा है। इसके बाद करीब छह महीने में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होंगे। इन कार्यक्रमों में जूडो-कराते, दंड अभ्यास, मलखंब जैसी शारीरिक ट्रेनिंग शामिल होगी। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर हथियार संचालन से जुड़ा प्रशिक्षण देने की भी योजना है।

ट्रेनिंग के लिए समिति से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मियों, सुरक्षा बल का अनुभव रखने वाले लोगों और मार्शल आर्ट प्रशिक्षकों की मदद ली जाएगी। अलग-अलग स्थानों पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसमें भाग ले सकें। समिति का दावा है कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और किसी भी अप्रिय स्थिति में खुद को संभालने में सक्षम होंगी।

संपादकीय

बजट: तस्वीर उतनी उजली नहीं

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश अपने नौवें वार्षिक बजट में दीर्घावधि विकास के जो सपने दिखाए गए हैं और वर्तमान में देश की जो आर्थिक हालत है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि तस्वीर उतनी उजली नहीं है, जितनी कि बताने की कोशिश की गई है। विपक्षी कांग्रेस ने तो इसे 'अंधा बजट' बताते हुए कहा कि इसमें मूल समस्याओं और जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही रोजगार, विकास और आर्थिक सर्वे को नजरअंदाज किया गया है। अगर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को विपक्ष की अपेक्षित प्रतिक्रिया मानकर दरकिनार करें तो भी केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा के मातृ संगठन आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संगठन और भारतीय किसान संगठन ने भी बजट को लेकर निराशा जताई है। उनका कहना है कि बजट में मजदूर और किसानों के लिए कुछ नहीं है। जाहिर है कि इस बजट में रेवड़ी बांटने जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ विशेषज्ञों की नजर में यह बजट बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2014 में जारी घोषणा पत्र की तरह वायदों का पुलिंदा है। बजट में अधिकांश योजनाओं का साल दो साल में तो अर्थव्यवस्था पर कोई असर दिखता प्रतीत नहीं होता। इसकी वजह दुर्लभ खनिज गलियारे से लेकर नए जलमार्गों के विकास तक लगभग सभी बड़ी परियोजनाओं के लागू होने की अवधि खासी लंबी होना है। इसी तरह रोजगार संवर्धन के दावे वाली पर्यटन सुविधाओं के विस्तार एवं उनके लिए टूरिस्ट गाइड आदि के प्रशिक्षण एवं पैरा मेडिकल सेवाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना अथवा विस्तार एवं क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए स्वदेशी डेटा सेंटरों की स्थापना संबंधी घोषणाओं के लागू होने में लंबा समय लगने की आशंका है।

यह सही है कि बजट की अधिकतर घोषणा अर्थव्यवस्था में दूरगामी परिवर्तनों की नीयत से की गई हैं जिनसे अगले वित्त वर्ष में तो कोई रोजगार बढ़ने अथवा पूंजी निवेश में तेजी आने की संभावना दिखाई नहीं देती। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि बजट में की गई ज्यादातर घोषणाएं वर्ष 2029 के आम चुनाव के मद्देनजर की गई प्रतीत होती हैं। इस राजनीतिक गुणाभाग से हटकर आर्थिकी की कसौटी पर कसें तो बजट का सीधा गणित यह है कि वर्ष 2026-27 के केन्द्रीय बजट में कुल 53 लाख 47 हजार 315 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इसका 24 फीसदी सरकार कर्ज लेकर जुटाएगी। बाकी रकम टैक्स और गैर कर स्त्रोतों से आएगी। सरकार जो खर्च करेगी, उसमें 20 फीसदी हिस्सा तो कर्ज चुकाने में जाएगा। 22 फीसदी भाग उगाहे गए कर्ज में से राज्यों का हिस्सा देने के रूप में, 11 प्रतिशत रक्षा खर्च और दो प्रतिशत केन्द्रीय कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च होगा। इसके अलावा केन्द्र सरकार के अपने प्रशासनिक खर्च भी हैं। इन सब के बाद पूंजीगत निवेश के लिए लगभग 17 लाख करोड़ रू. बचेंगे। केन्द्र सरकार अगले वित्त वर्ष में लगभग 17 लाख करोड़ के नए कर्ज लेगी। फिर भी 4.3 फीसदी का राजकोषीय घाटा बाकी रहेगा। हालांकि यह घाटा निर्धारित सीमा के भीतर ही रहेगा। मुद्दा यह है कि यदि देश का चौथाई बजट कर्ज चुकाने में खर्च हो रहा हो तो समझा जा सकता है कि देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है। पिछले साल भी सरकार ने 14 लाख करोड़ रू. का कर्ज लिया था। इस बार 3 लाख करोड़ रू. का ज्यादा कर्ज लेगी। इसका सीधा मतलब है कि सरकार कर्जा चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है। मप्र सहित ज्यादातर राज्य सरकारों की भी यही स्थिति है। जिस तेजी से कर्ज लिया जा रहा है, राजस्व संग्रहण उतना बढ़ नहीं पा रहा है। ऊपर से रेवड़ियां बांटनी पड़ रही हैं।

बदलता बांग्लादेश: चुनावों का भारत पर असर

नज़रिया

अंशुमान
लेखक संसद टीवी से जुड़े पत्रकार हैं।

बांग्लादेश एक लंबे और हिंसक संघर्ष के बाद अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले वहाँ एक अलोकतांत्रिक और दमनकारी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। इसके बाद करीब 18 महीनों तक ऐसा दौर चला, जब शासन कमजोर रहा और कानून-व्यवस्था लगातार बिगड़ती चली गई। अब देश 12 फरवरी को होने वाले अपने 13वें संसदीय चुनाव की ओर बढ़ रहा है। इसी दिन एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी कराया जाएगा, जिसमें देश की जनता पाँच अहम सवालों पर अपनी राय देगी। यह जनमत संग्रह संविधान में बदलाव से जुड़ा है, जिसकी माँग खास तौर पर युवाओं के आंदोलन से उठी थी।

तमाम उतार-चढ़ाव के बाद अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश में कई सामाजिक और राजनीतिक दरारें साफ़ दिखने लगी हैं। एक बार फिर से लोगों की पहचान से जुड़े सवाल फिर से चर्चा में आ गए हैं और अलग-अलग तरह के राष्ट्रवादी विचार खुलकर सामने आने लगे हैं। ऐसे माहौल में उम्मीद की जा रही है कि एक चुनी हुई सरकार देश को राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता की ओर ले जाएगी।

वैश्विक स्तर पर राजनीति पर नज़र रखने वाले जानकारों का भी मानना है कि यह चुनाव बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। चुनाव से पहले जिस तरह की हिंसा और तनाव देखने को मिल रहा है, उससे साफ़ संकेत मिलता है कि मुकाबला कड़ा और बेहद तीखा होगा। देश के करीब 12.7 करोड़ मतदाता, 300 संसदीय सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे लगभग 2000 उम्मीदवारों में से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। लेकिन असल सच्चाई यह है कि अवामी लीग के चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाने के कारण देश का राजनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल गया है। इस वजह से अब यह चुनाव मुख्य रूप से दो पुराने सहयोगी दलों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी यानी जेआई के बीच सीधी और निर्णायक लड़ाई बन गया है।

इन सबके बीच बीएनपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी नेतृत्व के उत्तराधिकारी तारिक रहमान पिछले महीने ढाका लौटे। उनके लौटने पर पार्टी समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बांग्लादेश के लिए अपनी योजना सामने रखी और लोगों से राष्ट्रीय एकता की अपील की, ताकि जनता की उम्मीदों को पूरा किया जा सके। साथ ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों से समान दूरी बनाए रखने की बात कही। मौजूदा राजनीतिक हालात में यह एक अहम संदेश माना जा रहा है। बीएनपी का चुनावी नारा सबसे पहले बांग्लादेश आम लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह दर्शाता है। हालांकि यह भी सही है कि पिछले 17 वर्षों से सत्ता और राजनीति के हाशिये पर रही इस पार्टी के लिए वापसी आसान नहीं है और इसके सामने कई मुश्किलें हैं। खुद को राजनीति के बीच वाले रास्ते यानी मध्यमार्गी विकल्प के रूप में पेश करने के लिए बीएनपी ने 10 दलों के गठबंधन का नेतृत्व करते हुए जमात-ए-इस्लामी से दूरी बनाने का फैसला किया।

दूसरी ओर, जमात-ए-इस्लामी, जो एक धार्मिक राजनीतिक दल है, अंतरिम सरकार के आने के बाद फिर से मजबूत हुई है। अब वह मुख्यधारा की राजनीति में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रही है। जमात को लगता है कि यह उसके लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि आने वाले समय में शायद उसे ऐसा अवसर फिर न मिले। इसी कारण उसने इस चुनाव में अवामी लीग को भाग लेने की अनुमति न देने की खुलकर मांग की, जबकि बीएनपी का रुख इस मुद्दे पर उतना सख्त नहीं रहा।

पिछले कुछ महीनों में हुए विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में अच्छी जीत के बाद जमात को भरोसा है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मौजूदगी मजबूत कर सकती है। जमात एक संगठित और आर्थिक रूप से मजबूत पार्टी है और वह 11 दलों के एक अलग गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। इसमें नई पार्टी नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) भी शामिल है। इससे युवाओं के बीच उसकी छवि जरूर बनी है, लेकिन जिन 32 सीटों पर यह पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहाँ बड़ी जीत की उम्मीद कम ही जताई जा रही है। जमात का नारा "चलो मिलकर बांग्लादेश बनाएँ" उसकी अपेक्षाकृत साफ़ और भ्रष्टाचार-मुक्त छवि पर ज़ोर देता है। लेकिन महिला उम्मीदवारों की पूरी तरह कमी और महिलाओं से जुड़े उसके सख्त विचार उसकी बड़ी कमजोरी हैं।

हालाँकि जमात के कुछ नेताओं ने भी प्रगतिवादी कदम के रूप में महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दफ्तरों में डे-केयर सेंटर और स्तनपान कक्ष जैसी सुविधाएँ देने की बातें कही हैं, लेकिन इन सबके बावजूद शहरी इलाकों और मध्यम वर्ग के मतदाता को भरोसेमंद नहीं मानते बल्कि उन्हें संदिग्धता से देखते हैं। जबकि देश की लगभग दो-तिहाई संसदीय सीटें शहरी क्षेत्रों में ही हैं। मीडिया सर्वे यह दिखाते हैं कि जमात को मिलने वाला समर्थन कुछ हद तक बढ़ा ज़रूर है, लेकिन अब भी वह बड़े पैमाने पर लोगों का भरोसा नहीं जीत पाई है। जमात को बीएनपी के साथ पुराने गठबंधन का फायदा मिल सकता है, खासकर उन सीटों पर जहाँ पहले बीएनपी ने उसे चुनाव लड़ने दिया था। सबसे बड़ा पहलू है अल्पसंख्यकों का और इसी को ध्यान रखते हुए और अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने की कोशिश में जमात ने दो हिंदू उम्मीदवार भी उतारे हैं। लेकिन अल्पसंख्यक मतदाता वास्तव में उसका समर्थन करेंगे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि दबाव और डर का इस्तेमाल, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ, अब भी कई पुराने और अनुभवी नेताओं का तरीका बना हुआ है।

विगत दिनों पर पीछे जाने पर बीएनपी की छवि भी हाल के महीनों में बहुत साफ़ नहीं रही है। कई बार स्थानीय स्तर पर जबरन वसूली और रिश्वतखोरी की खबरें सामने आई हैं। पार्टी के अंदर भी असंतोष है, क्योंकि पुराने नेताओं की जगह नए चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, 72 सीटों पर पार्टी से निकाले गए बीएनपी नेता स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे वोट बँटने की संभावना बढ़ गई है। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कई सीटों पर मुकाबला बीएनपी और उसके ही पूर्व नेताओं के बीच होगा। हालांकि इस बार माना जा रहा है कि लोग पार्टी के चुनाव चिन्ह से ज़्यादा उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि को देखकर वोट देंगे।

इस चुनाव में सबसे दिलचस्प यह देखना होगा कि इस बार बांग्लादेश में युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता कुल मतदाताओं का लगभग 35 प्रतिशत हैं और 2024 के आंदोलन, जवाबदेही की माँग और अच्छे शासन की उनकी अपेक्षाओं को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि उनका झुकाव किस ओर होगा। जातीय पार्टी आमतौर पर कम सीटें जीतने के बावजूद सत्ता में आने वाले गठबंधन का साथ देती रही है। इस बार नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से एक नया गठबंधन बना है, जिसमें जातीय पार्टी के दो गुट शामिल हैं। इन सबके बीच जीएम क़ादेर के नेतृत्व वाला गुट इससे बाहर है, जिससे चुनाव और भी अनिश्चित हो गया है।

हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रगतिशीलता दिखाते हुए पहली बार विदेशों में रहने वाले करीब चार लाख बांग्लादेशी नागरिकों को पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट देने की सुविधा दी है। इस बार मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से नहीं, बल्कि कागज़ी बैलेट से किया जाएगा। यह चुनाव केवल देश की अंदरूनी राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर बांग्लादेश के दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर भी पड़ेगा।

इन सबके बीच यह एकदम साफ है कि भारत के लिए भी मौजूदा हालात आसान नहीं हैं। पिछली बीएनपी सरकार के दौरान भारत को सुरक्षा से जुड़ी कई चिंताएँ थीं, जिन्हें वह अब भी नहीं भूला है। वहीं जमात-ए-इस्लामी का रुख खुलकर भारत विरोधी रहा है जो एक चिंता का विषय हो सकता है। हालाँकि हाल के महीनों में कई बांग्लादेशी नेताओं ने भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की बात कही है, लेकिन भारत की नीतियों से नाराज़ समूहों से निपटना नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। अवामी लीग के 15 साल के शासन और उसके बाद के पिछले 18 महीनों के अनुभवों ने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ भावनाओं को और तेज किया है। भारत इन चुनावों को पूरी तरह समावेशी नहीं मानता। अंतरिम सरकार द्वारा अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाए जाने से दिल्ली और ढाका के रिश्तों में दूरी बढ़ी है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री का खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होना बांग्लादेश में सकारात्मक रूप से देखा गया, लेकिन उनका यूनुस से मुलाकात न करना चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद क्रिकेट से जुड़ा एक विवाद सामने आया। फिर भारत द्वारा पूर्व अवामी लीग नेताओं को मीडिया से बातचीत की अनुमति देना जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान शेख हसीना का ऑनलाइन शामिल होना भी शामिल था, स्थिति को और बिगाड़ गया। इसका समय बेहद गलत था और इससे बांग्लादेश के बड़े हिस्से में नाराज़गी फैल गई।

चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली और ढाका अपने आपसी रिश्तों को नए सिरे से देखने और सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएँगे। बीते कुछ समय में दोनों देशों के संबंधों में जो तनाव और गलतफहमियां पैदा हुई हैं, उन्हें बातचीत और आपसी समझ से दूर करने की ज़रूरत होगी। स्थिर और भरोसेमंद रिश्ते न केवल भारत और बांग्लादेश, बल्कि पूरे क्षेत्र के हित में हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 2026 के संसदीय चुनाव बांग्लादेश के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होंगे। इन चुनावों का असर देश की आंतरिक राजनीति, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और शासन की दिशा पर तो पड़ेगा ही, साथ ही भारत समेत दूसरे देशों के साथ उसके संबंधों को भी नई दिशा मिलेगी।

शिक्षण संस्थानों में 'यूजीसी' के नए वैधानिक प्रयास

यूजीसी विवाद

डॉ. सुधीर कुमार
(हरियाणा के कुरुक्षेत्र विवि में सहायक प्रोफेसर)

यूजीसी ने हाल में प्रस्तावित 'उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव का उन्मूलन' नियम-2026 ने देशव्यापी वैचारिक घमासान छेड़ दिया। शिक्षा का प्रांगण वह नर्सरी है जहां राष्ट्र का भविष्य गढ़ा जाता है। यदि इसी आधारशिला में भेदभाव की दरारें दिखें, तो पूरे राष्ट्र का ढांचा डगमगा सकता है। जहां सरकार का लक्ष्य कैंपस को समावेशी और सुरक्षित बनाना है, वहीं इन नियमों के कुछ विशिष्ट प्रावधानों ने छात्र संगठनों और शिक्षकों में गहरा आक्रोश पैदा किया है। लोकतंत्र में नीतियों पर सवाल उठाना केवल आंदोलन नहीं, बल्कि सुधार की अनिवार्य प्रक्रिया है।

जातिगत भेदभाव को जड़ से मिटाने के पावन उद्देश्य से लाए गए 'यूजीसी भेदभाव-विरोधी नियम 2026' वर्तमान में समावेशिता के बड़े दावों और कानूनी अस्पष्टता के भंवर में फंस गए हैं। यदि हम इन नियमों के सकारात्मक पक्ष का अवलोकन करें, तो 'इक्विटी सेल' का गठन और 'एंटी-डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर' की नियुक्ति जैसे कदम निस्संदेह स्वागत योग्य हैं। ये प्रावधान कैंपस में उस जवाबदेही को संस्थागत रूप देते हैं, जिसकी कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। यह पहल एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास करती है जहाँ हर छात्र, चाहे उसका सामाजिक स्तर कुछ भी हो, खुद को सुरक्षित महसूस कर सके।

विवाद की मुख्य जड़ 'जाति' की संकुचित परिभाषा (नियम 3 सी) मेंनिहित है, जिसने सामाजिक ध्रुवीकरण को जन्म दिया है। जहाँ सामान्य वर्ग का तर्क है कि 'भेदभाव' किसी भी जाति के साथ हो सकता है और इसके दायरे में सभी को शामिल किया जाना चाहिए, वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में यह असुरक्षा है कि ओबीसी को समान श्रेणी में रखने से उनका 2012 के नियमों वाला विशेष संवैधानिक संरक्षण कमजोर हो जाएगा। यह स्थिति दर्शाती है कि सामाजिक न्याय जैसे संवेदनशील विषयों पर केवल सुधारवादी मंशा पर्याप्त नहीं है; इसके लिए व्यापक सर्वसम्मति, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और स्पष्ट वैधानिक परिभाषाओं का होना अनिवार्य है। छात्रों और शिक्षाविदों का मुख्य तर्क यह है कि प्रस्तावित नियमों में प्रयुक्त कुछ शब्दावलियां और प्रक्रियाएं कैंपस की स्वायत्तता को गंभीर चोट पहुँचा सकती हैं। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि नियमों का वर्तमान स्वरूप जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और यह वास्तविक न्याय के बजाय एक 'प्रशासनिक खानापूर्ति' या 'कागजी प्रक्रिया' बनकर रह जाएगा।

असंतोष की जड़ें उस ऐतिहासिक अविश्वास में हैं, जहाँ पीड़ित अक्सर न्याय के बजाय जटिल प्रक्रियाओं के जाल में उलझ कर रह जाता है। छात्रों की मांग केवल प्रतीकात्मक विरोध नहीं, बल्कि एक ऐसी पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली की है जहाँ शिकायतकर्ता को प्रशासन के दमन का भय न हो। सामाजिक न्याय के समर्थकों का यह तर्क भी महत्वपूर्ण है कि कैंपसों में जातिगत भेदभाव आज भी एक कड़वी हकीकत है। ऐसे में, सुरक्षात्मक नियमों को लचीला बनाना 'संवैधानिक गारंटी' के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। एक विश्वविद्यालय की आत्मा उसके शिक्षक और वहां की अकादमिक स्वतंत्रता में बसती जिन पर शोध और शिक्षण का पूरा दारोमदार होता है। किसी भी नए नियम का प्राथमिक उद्देश्य उन्हें 'अपराधी' की तरह कटघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा स्पष्ट ढांचा प्रदान करना होना चाहिए जिससे वे अपने संस्थान को एक आदर्श और न्यायपूर्ण समाज का छोटा स्वरूप बना सकें।

समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 का प्राण है। न्यायपालिका ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि शिक्षण संस्थानों में भेदभाव-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यहाँ 'विशाखा बनाम राजस्थान राज्य' (1997) के ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख करना प्रासंगिक है। यद्यपि वह मामला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि जहाँ कानून मौन या अस्पष्ट है, वहां संस्थानों को अपनी आंतरिक मार्गदर्शिका और समितियां बनानी चाहिए।

केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) (निजता का अधिकार) मामले में अदालत ने व्यक्ति की 'गरिमा' को मौलिक अधिकारों में सर्वोपरि माना था, और यूजीसी के 2026 के नियम इन्हीं संवैधानिक मूल्यों को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक साहसी प्रयास हैं। पूर्व की 'थोरत समिति' की रिपोर्ट और 'रोहित वेमुला' व 'डॉ पायल तड़वी' प्रकरण के बाद उपजी राष्ट्रीय संवेदनाओं ने यह अनिवार्य कर दिया था कि नियम केवल कागजी घोषणाएं न हों, बल्कि उनमें जवाबदेही और दंडात्मक प्रावधानों का एक स्पष्ट खाका मौजूद हो। यदि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार इन नियमों को वापस लेने या संशोधित करने पर विचार कर रही है, तो इसे नीतियों की विफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके विपरीत, इसे एक 'न्यायिक और लोकतांत्रिक सुधार' की उस सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए जो समाज की बदलती जरूरतों और व्यापक विमर्श के साथ खुद को परिष्कृत करती है।

वर्तमान में यूजीसी नियमों को लेकर उपजे विवाद और गतिरोध को दूर करने के लिए दंडात्मक दृष्टिकोण के बजाय सुधारात्मक मार्ग अपनाना कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध होगा। इसके लिए सबसे अनिवार्य कदम नियमों की परिभाषा में पूर्ण स्पष्टता लाना है, ताकि एक प्रोफेसर द्वारा किए गए 'अकादमिक मूल्यांकन' और 'जातिगत भेदभाव' के बीच का अंतर स्पष्ट रहे और शैक्षणिक आलोचना को भेदभाव का रंग न दिया जा सके। साथ ही, इन नियमों की सफलता के लिए स्वतंत्र आंतरिक समितियों की विश्वसनीयता सर्वोपरि है, जिसमें केवल प्रशासन ही नहीं बल्कि बाहरी विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और पारदर्शी तरीके से चुने गए छात्र प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि 'हितों के टकराव' की संभावना न रहे।

'न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर है' के सिद्धांत पर चलते हुए, किसी भी शिकायत का निपटारा अधिकतम 30 दिनों की समयबद्ध सीमा में होना चाहिए, जिससे पीड़ितों का भरोसा बढ़े और झूठी शिकायतों पर अंकुश लगे। अंततः केवल दंड के भय से समाज को नहीं बदला जा सकता; इसके लिए कैंपसों में निरंतर अंतराल पर जातिगत, सामाजिक और लैंगिक संवेदनशीलता पर कार्यशालाएं अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि शिक्षकों और छात्रों के मन में एक-दूसरे के प्रति स्वाभाविक सम्मान का भाव जागृत हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार इन नियमों में बड़े संशोधनों या इन्हें वापस लेने पर विचार कर रही है। इसे प्रशासन की 'हार' के बजाय एक 'संवेदनशील और उत्तरदायी सरकार' के परिपक्व लक्षण के रूप में देखा जाना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती ही इसमें है कि नीतियों को जनभावनाओं के अनुरूप पुनर्विचार के लिए खुला रखा जाए।

यूजीसी का यह पूरा प्रकरण हमें एक बड़ा पाठ सिखाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी युगांतकारी परिवर्तन बिना प्रमुख हितधारकों (छात्र, शिक्षक और प्रशासन) के सक्रिय परामर्श के सफल नहीं हो सकता। समानता का मार्ग सड़कों पर संघर्ष से नहीं, बल्कि मेज पर बैठकर किए गए सार्थक संवाद से ही प्रशस्त होता है। यदि सरकार एक नई 'सर्वपक्षीय ड्राफ्टिंग कमेटी' का गठन कर शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों को इसमें स्थान देती है, तो यह भारतीय उच्च शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। हमारा अंतिम लक्ष्य एक ऐसा प्रबुद्ध भारत बनाना है जहाँ किसी भी युवा की जाति, धर्म या लिंग उसकी प्रतिभा के मार्ग में रोड़ा न बने और न ही किसी शिक्षक की गरिमा पर कोई आंच आए। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति को होता हुआ दिखना भी चाहिए। अब समय है कि हम 'दबाव' की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर 'दस्तावेज' की दूरदर्शी राजनीति करें, जहाँ नियमों का हर शब्द एक समावेशी और समतामूलक भारत की तस्वीर पेश करे।

सच और झूठ की पहचान का संकट

एआई का दौर

संध्या अग्रवाल
लेखक जबलपुर निवासी साहित्यकार हैं।

आज का समय सूचनाओं से भरा हुआ है, लेकिन सच की पहचान पहले से कहीं अधिक कठिन हो गई है। एक दौर था जब खबरें सीमित माध्यमों से आती थीं और उन पर भरोसा करना अपेक्षाकृत सहज था। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर स्क्रीन पर सूचनाओं की भरमार है। इस बाढ़ में सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो गई है कि कई बार हम स्वयं भी भ्रमित हो जाते हैं।

आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जीवन को तेज़ और सुविधाजनक बनाया है। तकनीक ने काम आसान किए हैं, समय बचाया है और संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। लेकिन इसके साथ ही एक गंभीर प्रश्न भी खड़ा हुआ है—क्या जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, वह सच है? आज तस्वीरें बदली जा सकती हैं, आवाज़ों की नकल संभव है और वीडियो तक गढ़े जा सकते हैं। ऐसे में आँखों देखा भी अब पूरी तरह विश्वसनीय नहीं रहा।

सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि हम खबरों को समझने से पहले साझा करने लगे हैं। किसी संदेश पर 'ब्रेकिंग' या 'देखिए सच्चाई' लिखा हो, तो हम बिना ठहरे उसे आगे बढ़ा देते हैं। यह जल्दबाज़ी हमें सोचने का अवसर नहीं देती। धीरे-धीरे यह आदत बन जाती है और हम स्वयं जाने-अनजाने झूठ के प्रसार का माध्यम बन जाते हैं। एक क्लिक, एक फ़ॉरवर्ड—और असत्य कई लोगों तक पहुँच जाता है।

एआई के दौर में सबसे बड़ा संकट हमारे विवेक पर आया है। जब मशीनें सोचने लगी हैं, तब मनुष्य सोचने से बचने लगा है। हम मान लेते हैं कि जो वायरल है, जो बार-बार सामने आ रहा है, वही सच होगा। जबकि सच तक पहुँचना अब पहले से अधिक धैर्य और सजगता की माँग करता है। सत्य अब सहज नहीं, विवेकपूर्ण प्रयास से ही सामने आता है।

आज यह आवश्यक हो गया है कि हम हर सूचना को निष्पक्ष दृष्टि से देखें। यह जानने की कोशिश करें कि स्रोत क्या है, खबर किसने दी है और क्या अन्य विश्वसनीय माध्यम भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं। भावनाओं को भड़काने वाली सूचनाओं से विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। ये प्रश्न अब केवल जागरूक लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए अनिवार्य हो चुके हैं।

सच और झूठ की पहचान केवल पत्रकारों या विशेषज्ञों की जिम्मेदारी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो किसी सूचना को पढ़ता, देखता या साझा करता है। आज हर व्यक्ति अपने स्तर पर एक छोटा माध्यम बन चुका है। ऐसे में उसकी सजगता या लापरवाही, दोनों का असर समाज पर पड़ता है। झूठ केवल भ्रम नहीं फैलाता, वह विश्वास को भी कमजोर करता है—रिश्तों में, समाज में और संस्थाओं में।

यह भी समझना आवश्यक है कि तकनीक स्वयं न अच्छी होती है, न बुरी। उसका स्वरूप हमारे उपयोग से तय होता है। एआई हमारे लिए एक साधन है, निर्णयकर्ता नहीं। निर्णय लेने का अधिकार हमें अपने विवेक के पास ही रखना होगा। यदि हमने यह अधिकार मशीनों को सौंप दिया, तो धीरे-धीरे हम स्वयं सोचने की क्षमता खो बैठेंगे।

सच अक्सर शोर नहीं करता। वह शांत रहता है, लेकिन टिकाऊ होता है। झूठ इसके विपरीत तेज़ और आकर्षक होता है, पर भीतर से खोखला। चुनौती यही है कि हम चमक के पीछे न भागें, बल्कि ठहरकर सत्य को पहचानने का प्रयास करें।

एआई के इस दौर में यदि हम सोचने की आदत, प्रश्न पूछने का साहस और तथ्य जाँचने की संवेदनशीलता बचा पाए, तो सच भी सुरक्षित रहेगा। तकनीक के साथ चलना ज़रूरी है, लेकिन आँख मूँदकर नहीं। क्योंकि समाज की दिशा अंततः मशीनें नहीं, मनुष्य का विवेक ही तय करता है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

जल है तो कल है, मगर कल किसने देखा!

व्यंग्य

डॉ. श्रीकांत द्विवेदी
लेखक व्यंग्यकार हैं।

माध्यमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक हिंदी के प्रश्न पत्र में 'जल ही जीवन है' जैसे विषय पर एक निबंध अक्सर पूछ लिया जाता है। ज्यादातर विद्यार्थी इस विषय पर अच्छे से निबंध लिख लेते हैं। मगर, अब बदलते संदर्भों में निबंध का विषय भी बदला जा सकता है। नए पैटर्न में 'प्रदूषित जल, समस्या और समाधान' जैसे विषय पर ही निबंध लिखवाना उचित होगा। कारण, यूं तो जल जीवन है, मगर इन दिनों मौत की वजह भी बनता जा रहा है। ऐसे में पंच तत्वों से बनी मानव देह में जब हवा-पानी दोनों ही प्रदूषित हो जाए तो फिर क्या बचता है। कुछ नहीं बचता। सिर्फ गरुड़ पुराण ही बचता है।

माना कि भारत भूमि कभी पानीदार भूमि भी रही है। यहां की पावन नदियों में रोग निवारण की क्षमता होती थी। समय के साथ-साथ पानीदार भूमि का पानी कब बोतलों में बंद हो गया, पता ही नहीं चला। जबकि, ज्यादातर पावन नदियां अपने ही रोग निदान की आस लगाए बैठी हैं। तभी तो बरसों पूर्व कविवर रहीम को लिखना पड़ा था कि 'रहिमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती-मानुष चून।।' लिखना इसलिए पड़ा कि रहीम दूरदृष्टा थे। उन्हें पता था कि यदि पानी को सहेजकर नहीं रखा, तो यही पानी एक दिन जानलेवा साबित हो जाएगा। ठीक है, यह सोच करीब चार सदी से भी पहले का रहा होगा। उस दौर में भक्तिकाल था। तब विकास की कोई कल्पना नहीं थी। केवल भक्ति से तो विकास संभव नहीं था।

समय का पहिया घूमता गया। अब भक्तिकाल की जगह शक्तिकाल ने ले ली। मशीनी शक्ति के बल पर जल, जंगल और जमीन के स्वरूप पूरी तरह से बदल गए। कुएं-बावड़ी पाट दिए। संकरी गलियों तक नाली के किनारे-किनारे नल की पाइप लाइन के जाल बिछ गए। इतनी सुविधाओं से भी जब लोगों का मन नहीं भरा तो दो-चार कमरे के मकान में भी किचन से सटे अटैच लेट-बाथ बना डाले। साथ ही चार-छः फीट के अंतर से वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक भी बना डाले। मात्र इतना ही नहीं पानी की बड़ी-बड़ी टंकियां बनी। कब साफ होती है, किसी को पता नहीं। बस्तियों में ड्रेनेज भी बने। ऐसे में थोड़ा बहुत पेयजल प्रदूषित होना स्वाभाविक है। विकास के लिए इतना तो सहना ही पड़ता है।

बस, इतनी सी बात पर इतना बवाल। बवाल भी उनके खिलाफ, बवाल भी इंदौरी शान के खिलाफ। अरे, इंदौरी शान ही है जिसने देश-विदेश के विशिष्ट जन का आतिथ्य सत्कार कर इंदौरी पोहे-जलेबी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। अगर नलों में एक दम साफ पानी नहीं भी आया, तो मन मारना था। साफ पानी नहीं है तो क्या, आपके लिए मेट्रो ट्रेन है। हो सकता है, अगले चुनाव तक आपके नलों से मिनरल वाटर मिलने लग जाए। रही बात दूषित पानी पीने से लेकर हुई मौतों की, तो इस बात का जिम्मेदारों को भी उतना ही दुःख है, जितना शोकाकुल परिवारों को। इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे। बोलते हैं, तो गला रूंध जाता है। ऐसे में मीडिया वाले जबरदस्ती बुलवाने का प्रयास करते हैं तो फिर व्यथित मुख से कुछ का कुछ निकल जाना स्वाभाविक है।

यह भी सत्य है कि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया, उसका एक दिन मरण निश्चित है। देह नाशवान है। आत्मा अमर है। क्योंकि, आत्मा को दूषित पानी मार नहीं सकता। जुबानी तलवार काट नहीं सकती और विरोध की आग कभी जला नहीं सकती। इसलिए हे पीड़ित जन! थोड़ा धैर्य रखें। आपके क्षेत्र की कूनो नेशनल पार्क से भी ज्यादा देखभाल होगी। हर घर के आगे शीघ्र ही एक नई पाइप लाइन होगी। फिलहाल टैंकरों से प्रदत्त पानी से काम चला लें। कारण जल है तो कल है। वैसे जल तो है, मगर कल किसने देखा!

कानून और न्याय

विनय झैलावत
(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

प्रचार का कानूनी अधिकार और सेलिब्रिटी की पहचान

देश में प्रचार का कानूनी अधिकार (राइट्स ऑफ़ पब्लिसिटी) सेलिब्रिटी को अपने नाम, छवि, आवाज या पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने और अनधिकृत व्यावसायिक लाभ को रोकने की अनुमति देता है। यह अधिकार संवैधानिक निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) और ट्रेडमार्क कानून के अंतर्गत संरक्षित है, जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मशहूर हस्तियों के व्यक्तित्व के अनधिकृत उपयोग (एआई, नकली विज्ञापन) के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

हाल ही अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन सहित कई प्रसिद्ध हस्तियों के प्रस्तुत मुकदमों से यह स्पष्ट हुआ कि व्यक्तित्व अधिकार और प्रचार अधिकार की अवधारणाओं को लेकर कानूनी चर्चा में काफी भ्रम है। न्यायालयों ने व्यक्तित्व अधिकार और प्रचार अधिकार की व्याख्या और प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किए, लेकिन इनमें से किसी की भी कोई ठोस परिभाषा निर्धारित नहीं की। व्यक्तित्व अधिकारों और प्रचार अधिकारों के बीच अंतर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भी निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या इन दोनों के बीच कोई परस्पर संबंध है या नहीं! कुछ समय पहले जैकी श्रॉफ समेत कई हस्तियों ने ऐसे मामले उठाए थे। हम विश्लेषण करते हैं कि न्यायिक व्याख्या ने इन अधिकारों को किस प्रकार आकार दिया है। इसके परिणामस्वरूप एक विकृत सेलिब्रिटी-केंद्रित ढांचा और आम व्यक्तियों के लिए समस्याग्रस्त बहिष्करण हुआ है। इस मुद्दे के मूल में यह आवश्यकता निहित है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित निजता और गरिमा के मौलिक अधिकार से अलग किया जाए।

महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कोई भी कानून व्यक्तित्व अधिकारों या प्रचार अधिकारों को परिभाषित नहीं करता। इससे न्यायालयों को सामान्य कानून और मौजूदा न्यायिक मिसाल के माध्यम से इन अवधारणाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी मिलती है। समस्या यहीं निहित है। न्यायालय किसी भी वैधानिक परिभाषा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसके कारण वे मामले के तथ्यों के आधार पर उदार व्याख्या करते हैं और परिभाषाएं देते हैं।

सामान्यतः व्यक्तित्व अधिकारों में व्यक्ति का नाम, आवाज, हस्ताक्षर, फोटो, छवि, व्यंग्यचित्र, समानता, व्यक्तित्व और उसके व्यक्तित्व के अन्य विभिन्न गुण शामिल होते हैं। दूसरी ओर, प्रचार अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यावसायिक रूप से दोहन करने का अनन्य अधिकार है (टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मेसर्स रामकुमार ज्वैलर्स)।

इस अंतर के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व अधिकारों को प्रचार अधिकारों का एक उपसमूह समझा जाना चाहिए, जिसमें व्यक्तित्व अधिकार और अन्य व्यावसायिक अधिकार शामिल हैं। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि प्रचार अधिकार एक प्रकार के संपत्ति अधिकार हैं। न्यायालयों द्वारा व्यक्तित्व अधिकारों की व्याख्या करने का तरीका किसी व्यक्ति के निजता अधिकारों की मात्र सुरक्षा के बजाय, सेलिब्रिटी पहचान के व्यवसायीकरण की सुरक्षा को दर्शाता है, जैसा कि न्यायालयों के पूर्व निर्णयों में परिकल्पित किया गया था। इसमें न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ का मामला भी शामिल है। कई वर्षों के दौरान, व्यक्तित्व अधिकारों की परिभाषा और व्याख्या में एक व्यापक परिवर्तन आया है। पहले यह व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकार पर आधारित स्वायत्तता संरक्षण की अवधारणा थी, लेकिन अब इसका स्वरूप व्यवसायीकरण हो गया है।

व्यक्तित्व अधिकारों की वर्तमान समझ को प्रचार अधिकार कहा जाता है। क्योंकि न्यायिक मिसालों में व्यक्तित्व अधिकारों को मुख्य रूप से केवल मशहूर हस्तियों से जुड़े मामलों में ही मान्यता दी गई है। इससे एक तरह से केवल मशहूर हस्तियों तक ही सीमित ढांचा बन गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐश्वर्या राय बच्चन बनाम और अन्य के मामले में पारित एक आदेश में कहा कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का उपयोग उनकी सहमति या अनुमति के बिना किया जाता है, तो इससे न केवल संबंधित व्यक्ति को व्यावसायिक नुकसान हो सकता है, बल्कि उनके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर भी असर पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों का अनधिकृत शोषण दो पहलुओं को जन्म दे सकता है। पहला, उनके व्यक्तित्व के गुणों को व्यावसायिक रूप से शोषण से बचाने के अधिकार का उल्लंघन और दूसरा, उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन, जो बदले में उनके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को कमजोर करता है।

इस परिभाषा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यक्तित्व अधिकारों में व्यक्ति के वे गुण शामिल हैं जिनका व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें उनकी निजता का अधिकार भी शामिल है। यह परिभाषा व्यक्तित्व अधिकारों को प्रचार अधिकारों के लगभग समान बना देती है। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस व्याख्या के कारण, अपने व्यक्तित्व अधिकार को लागू करने या संरक्षित करने का विकल्प अब केवल मशहूर हस्तियों या प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है। हालांकि, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए, चाहे उनके पास मुद्रीकरण योग्य सेलिब्रिटी व्यक्तित्व हो या न हो। लेकिन, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इन मुकदमों को दायर करने वाले अधिकांश सेलिब्रिटी याचिकाकर्ता वास्तविक सुपरस्टार हैं।

उन्होंने तीन मुख्य तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, झूठे समर्थन और झूठे विज्ञापन का दावा है। उनका तर्क है कि उनकी व्यक्तिगत पहचान के अनधिकृत उपयोग के कारण जनता को यह भ्रम हुआ है कि उन्होंने किसी उत्पाद, ऑडियो-विजुअल सामग्री, वेबसाइट या कार्यक्रम को प्रायोजित या समर्थन दिया है। दूसरा, एआई उपकरणों (मॉर्फ्ड तस्वीरें, डीपफेक, जीआईएफ आदि) का उपयोग करके आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरों में उनकी व्यक्तिगत पहचान के अनधिकृत उपयोग से उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है। तीसरा, इस तरह के उपयोग उनके निजता के अधिकार और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। संक्षेप में, जिस नुकसान से वे बचाव करना चाहते हैं, उसमें गलत बयानी, छवि धूमिल होने से नुकसान और मानहानि शामिल हैं। विडंबना यह है कि निजता के उल्लंघन से लेकर आजीविका के नुकसान तक के इनमें से कई दावे उन मशहूर हस्तियों की ओर से आते हैं जिनकी आजीविका लोगों की नजरों में आने पर निर्भर करती है।

व्यक्तिगत अधिकारों और प्रचार अधिकारों के बीच अंतर करना केवल शब्दावली के आधार पर ही आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीएम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम बेबी गिफ्ट हाउस मामले में प्रचार अधिकारों को संक्षेप में समझाया कि प्रचार का अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनधिकृत दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित व्यावसायिक लाभ प्राप्त हो सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इस संदर्भ में अधिकांश न्यायशास्त्र व्यक्तित्व अधिकारों के बजाय ट्रेडमार्क अधिकारों के क्षेत्र में रहा है। लेकिन ये मामले निजी अधिकारों और व्यापक जनहित के बीच संतुलन स्थापित करने के मामले में शिक्षाप्रद हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक के आगमन के साथ, केवल हस्तियाँ ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील अन्य समूह भी प्रभावित हो रहे हैं।

यदि कोई आम व्यक्ति, जो डीपफेक का शिकार हुआ है, अपने व्यक्तित्व अधिकारों को लागू करने का प्रयास करता है, तो व्यक्तित्व अधिकारों की वर्तमान व्याख्या उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। उसके पास केवल आपराधिक उपाय ही बचेंगे क्योंकि वह कोई सार्वजनिक हस्ती या सेलिब्रिटी नहीं है। यह दुविधा आसानी से हल हो सकती है यदि व्यक्तित्व अधिकारों और प्रचार अधिकारों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाए। यह अंतर अंतर्निहित व्यावसायिक हितों/अधिकारों के आधार पर किया जा सकता है। व्यक्तित्व अधिकारों को गरिमापूर्ण अधिकारों के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए, जो अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के एक उपसमूह के रूप में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, चाहे उनका वाणिज्यिक मूल्य कुछ भी हो। इसके विपरीत, प्रचार अधिकारों को बौद्धिक संपदा के समान विशिष्ट वाणिज्यिक अधिकारों के रूप में माना जाना चाहिए, जो हस्तांतरणीय और त्यागने योग्य हों।

बजट 2026

कुमार सिद्धार्थ
लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के साझा मॉडल की परिकल्पना

केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा को लेकर सरकार ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव कक्षा, कौशल और तकनीक के मेल से रखी जाएगी। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार शिक्षा पर कुल आवंटन बढ़ाकर लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 1.28 लाख करोड़ रुपये की तुलना में करीब 8.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। पहली नज़र में यह बढ़ोतरी उल्लेखनीय लगती है और सरकार इसे भविष्य की तैयारी के रूप में प्रस्तुत कर रही है, लेकिन गहराई से देखने पर यह सवाल भी सामने आता है कि क्या यह बजट वास्तव में पुरानी संरचनात्मक समस्याओं से किनारा करता है या उन्हें नई शब्दावली में ढक देता है।

इस बजट का केंद्रीय विचार शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को एक साझा रणनीति के रूप में जोड़ने का है। सरकार का मानना है कि केवल डिग्री आधारित शिक्षा अब पर्याप्त नहीं है, इसलिए पाठ्यक्रमों को उद्योग, तकनीक और वैश्विक ज़रूरतों से जोड़ना आवश्यक है। इसी सोच के तहत स्कूलों और कॉलेजों में कौशल आधारित ढांचे को मजबूत करने की घोषणाएँ की गई हैं। सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला प्रस्ताव 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करने का है। एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों को भविष्य के रोजगार से जोड़ते हुए सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि डिजिटल और क्रिएटिव इकोनॉमी अब औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनेगी।

बजट दस्तावेज़ों में यह भी उल्लेख है कि वर्ष 2030 तक एवीजीसी और इससे जुड़े डिजिटल क्रिएटिव सेक्टर में लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार की आवश्यकता होगी। ऐसे में स्कूल स्तर से ही कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और तकनीकी कौशल सिखाने की योजना को सरकार एक दूरदर्शी कदम के रूप में पेश कर रही है। इससे युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजन में सक्षम बनाने का दावा किया गया है।

उच्च शिक्षा के मोर्चे पर बजट का झुकाव तकनीक, अनुसंधान और उद्योग से सीधे जुड़ाव की ओर दिखाई देता है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास पाँच यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार का तर्क है कि जब विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर, स्किल हब और उद्योग एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होंगे, तो छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव, इंटर्नशिप और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह मॉडल शिक्षा और उद्योग के बीच लंबे समय से चली आ रही दूरी को पाटने का प्रयास है।

बजट में यह भी कहा गया है कि शिक्षा को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए एक उच्च-स्तरीय स्थायी समिति गठित की जाएगी। यह समिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और उभरती तकनीकों के संदर्भ में यह आकलन करेगी कि भविष्य में कौशल और रोजगार की ज़रूरतें कैसे बदलेंगी और उसी अनुसार पाठ्यक्रमों में सुधार की सिफारिश करेगी। यह पहल संकेत देती है कि सरकार शिक्षा नीति को स्थिर नहीं, बल्कि बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप लचीला बनाना चाहती है।

हालाँकि, इन घोषणाओं के समानांतर कुछ बुनियादी प्रश्न भी खड़े होते हैं। बजट विश्लेषण में यह तथ्य सामने आता है कि शिक्षा पर कुल खर्च अभी भी जीडीपी के लगभग 2.8 से 3 प्रतिशत के आसपास ही बना हुआ है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसे कम से कम 6 प्रतिशत तक ले जाने की बात वर्षों से कही जाती रही है। इस दृष्टि से देखें तो 8.6 प्रतिशत की नाममात्र वृद्धि वास्तविक ज़रूरतों के सामने सीमित प्रतीत होती है, खासकर तब जब छात्र संख्या लगातार बढ़ रही है और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की मांग तेज़ है।

स्कूल शिक्षा के संदर्भ में बजट में डिजिटल और तकनीकी अवसंरचना पर ज़ोर दिखाई देता है। डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन संसाधन और नई तकनीकों के माध्यम से शिक्षा को सुलभ बनाने की बात कही गई है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूलों की भौतिक सुविधाएँ और ग्रामीण-आदिवासी क्षेत्रों की ज़मीनी हकीकत इस डिजिटल छलांग के साथ तालमेल बिठा पाएगी। कई विश्लेषणों में यह चिंता भी जताई गई है कि यदि शिक्षक ही प्रशिक्षित नहीं होंगे, तो स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल लैब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धूल ही फाँकेंगे।

राज्य विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों की स्थिति पर बजट अपेक्षाकृत मौन दिखाई देता है। जबकि देश के लगभग 80 प्रतिशत विद्यार्थी इन्हीं संस्थानों में पढ़ते हैं, अनुसंधान और बुनियादी सुविधाओं के लिए मिलने वाला अधिकांश फंड अब भी केंद्रीय और प्रीमियम संस्थानों तक सीमित रहता है। इस असंतुलन के कारण राज्य विश्वविद्यालयों में शोध संस्कृति कमजोर होती जा रही है और बजट में इस खाई को पाटने के लिए कोई ठोस रोडमैप साफ़ नज़र नहीं आता।

बजट में यह भी उल्लेख है कि शिक्षा, कौशल और रोजगार को जोड़कर 'भविष्य की अर्थव्यवस्था' की नींव रखी जा रही है। युवाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करने की बात कही गई है और इसे जनसांख्यिकीय लाभांश से जोड़ा गया है। भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और सरकार इस युवा शक्ति को उत्पादक मानव संसाधन में बदलने का लक्ष्य रखती है। लेकिन यह लक्ष्य तभी साकार होगा जब शिक्षा केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित न रहे, बल्कि आलोचनात्मक सोच, सामाजिक संवेदनशीलता और रचनात्मकता को भी स्थान दे।

कुल मिलाकर, बजट 2026-27 का शिक्षा खंड एक दोहरे संदेश के साथ सामने आता है। एक ओर यह तकनीक, कौशल और रोजगार के ज़रिये भविष्य की तैयारी की बात करता है, दूसरी ओर यह पुरानी समस्याओं जैसे अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश, शिक्षक भर्ती की कमी और राज्य स्तरीय संस्थानों की उपेक्षा से पूरी तरह मुक्त होता नहीं दिखता। यह बजट शिक्षा को आर्थिक विकास के औज़ार के रूप में तो देखता है, लेकिन उसे सामाजिक समानता और बौद्धिक स्वतंत्रता के व्यापक संदर्भ में रखने का साहस अभी अधूरा लगता है।

आख़िरकार, यह कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा बजट 2026-27 दिशा तो दिखाता है, लेकिन दूरी अभी तय होनी बाकी है। यह भविष्य की तैयारी का दावा करता है, पर साथ ही यह सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या हम पुरानी समस्याओं को हल किए बिना सचमुच एक समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ पाएँगे?

बजट 2026

डॉ. सत्येंद्र किशोर मिश्र
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

कर्तव्यों के साथ संभावनाओं का बजट

बजट बढ़ते व्यापार और पूंजी की जरूरतों के साथ, भारत को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करते हुए अधिक निर्यात तथा स्थिर दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करता है। बजट में, विकसित भारत की राह में आर्थिक सुधारों के साथ आर्थिक संवृद्धि की रफ्तार बनाए रखते हुए रणनीतिक और सीमांत क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ाने; पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने; चैंपियन एमएसएमई बनाना; बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत प्रोत्साहन देने; दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने; और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करने की प्रतिबद्धता है। बजट में नियामक सुधारों, एक मजबूत समष्टि बुनियाद तथा निवेश हेतु निजी क्षेत्र के आह्वान के साथ वित्तीय वर्ष 2026–27 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.4 फीसद तथा वित्तीय वर्ष 2027–28 में 6.8 से 7.2 फीसद वृद्धि की संभावना के साथ आर्थिक विकास तथा राजकोषीय समेकन के प्रति प्रतिबद्धता भी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजकोषीय घाटा भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 फीसद था, जिसे वित्त वर्ष 2026–27 में 4.3 फीसद से कम रखने का लक्ष्य है।

केंद्रीय बजट 2026-27, आधुनिक तकनीक एवं बदलते उत्पादन प्रणालियों के मध्य महत्वाकांक्षा और समावेशिता में संतुलन साधते हुए विकसित भारत की उम्मीदों से प्रेरित है। बजट वैश्विक अनिश्चितता के दौर में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को तेज़ तथा बनाए रखने; जनाकांक्षाओं को पूरा करते हुए सबका साथ, सबका विकास की दृष्टि के अनुरूप है। सतत आर्थिक सुधारों पर आधारित प्रयासों से एक दशक में लगभग 25 करोड़ आबादी गरीबी से बाहर आ चुकी है। बजट युवाओं, गरीबों, वंचितों और कमजोर लोगों पर केन्द्रित है। शेयर बाजार की तात्कालिक प्रतिक्रिया से इस बजट का मूल्याकन करने के बजाय इसे विकसित भारत की दिशा में बढ़ता आत्मविश्वास भरे प्रयास के रूप में समझने की जरूरत है।

बजट बढ़ते व्यापार और पूंजी की जरूरतों के साथ, भारत को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करते हुए अधिक निर्यात तथा स्थिर दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करता है। बजट में, विकसित भारत की राह में आर्थिक सुधारों के साथ आर्थिक संवृद्धि की रफ्तार बनाए रखते हुए रणनीतिक और सीमांत क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ाने; पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने; चैंपियन एमएसएमई बनाना; बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत प्रोत्साहन देने; दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने; और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करने की प्रतिबद्धता है।

बजट में नियामक सुधारों, एक मजबूत समष्टि बुनियाद तथा निवेश हेतु निजी क्षेत्र के आह्वान के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.4 फीसद तथा वित्तीय वर्ष 2027-28 में 6.8 से 7.2 फीसद वृद्धि की संभावना के साथ आर्थिक विकास तथा राजकोषीय समेकन के प्रति प्रतिबद्धता भी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 फीसद था, जिसे वित्त वर्ष 2026-27 में 4.3 फीसद से कम रखने का लक्ष्य है। बजट में ऋण-जीडीपी अनुपात घटकर 55.6 फीसद रहने का अनुमान है, यह निवेशकों, रेटिंग एजेंसियों और वैश्विक बाजार को भारत में आर्थिक स्थिरता का आश्वासन है।

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु विनिर्माण, पर्यटन, दुर्लभ-पृथ्वी खनन और नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। बजट में पूंजीगत वस्तुओं की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर है। उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण केन्द्र स्थापित करने तथा इलेक्ट्रानिक विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु रू.40,000 करोड़ का प्रस्ताव है। विनिर्माण क्षेत्र में भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने हेतु, अगले पांच वर्षों में रू.10,000 करोड़ के प्रावधान के साथ बायोफार्मा शक्ति स्थापित की जाएगी। श्रम-प्रधान कपड़ा क्षेत्र में एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित है, प्राकृतिक फाइबर जैसे रेशम, ऊन और जूट, मानव निर्मित फाइबर, और नए ज़माने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना; मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों हेतु पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी। मेगा टेक्सटाईल पार्क तथा तीन रासायनिक पार्क बनाने का प्रस्ताव है। एमएसएमई को विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में पहचानते हुए, भविष्य के एमएसएमई चैंपियन बनाने हेतु रू.10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड प्रस्तावित है, जो चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करेगा। दो सौ औद्योगिक पार्कों को पुर्नजीवित किया जाएगा तथा खादी, हथकरघा तथा हस्तशिल्प को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी स्वराज योजना आरंभ की जाएगी।

आधारभूत संरचनाओं के विकास के तहत पर्यावरण के अनुकूल कार्गो की सस्टेनेबल आवाजाही को बढ़ावा देने हेतु दानकुनी को सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा अगले 5 सालों में 20 नए नेशनल वॉटरवे चालू करने का प्रस्ताव है। सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को 'ग्रोथ कनेक्टर' के तौर पर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी विकसित करेगा। ज़रूरी मैनपावर के डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को रीजनल सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस के तौर पर बनाया जाएगा। बजट, शहरों की क्षमता को और बढ़ाकर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की मैपिंग कर एग्लोमेरेशन्स को इकोनॉमिक पावर देगा। रिफॉर्म-कम-रिजल्ट्स बेस्ड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के साथ चैलेंज मोड के ज़रिए अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए 5 वर्षों में प्रत्येक रीजन के लिए रू.5000 करोड़ का आवण्टन प्रस्तावित है।

पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप निर्माण में सहायता की जाएगी। डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी तथा देश के प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास खोले जाएंगे। खेल रोजगार तथा कौशल का अवसर प्रदान करती है। युवा विकास हेतु खेलो इंडिया मिशन के ज़रिए शुरू किए गए स्पोर्ट्स टैलेंट को सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाते हुए, खेलों पर जोर देने का प्रस्ताव है। खेलो इंडिया मिशन को दस वर्षों तक बढ़ाते हुए प्रतिभा विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षक विकास, खेल चिकित्सा को बढ़ावा देगा। भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, जिसके लिए वर्ष 2030 तक बीस लाख प्रोफेशनल्स की आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। बजट में 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़, मुंबई की सहायता ली जाएगी। मौजूदा नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हॉस्पिटैलिटी बनाने का प्रस्ताव, एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सरकार के मध्य ब्रिज का काम करेगा। बजट में भारतीय प्रबंध संस्थान के साथ मिलकर हाइब्रिड मोड में एक स्टैंडर्ड, हाई-क्वालिटी 12-हफ़्ते के ट्रेनिंग कोर्स के ज़रिए 20 टूरिस्ट जगहों पर 10,000 गाइड को अपस्किल करने के लिए एक पायलट स्कीम का भी प्रस्ताव है। पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन, स्थानीय क्षेत्र विकास तथा विदेशी आय अर्जन को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय हॉस्पिटलिटी संस्थान की स्थापना तथा 15 पुरातात्विक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। सांस्कृतिक-ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का डिजिटल केन्द्र प्रस्तावित है। विश्वस्तरीय हाई ट्रैकिंग का निर्माण किया जाएगा, दस हजार गाइडों का कौशल उन्नयन किया जाएगा।

विकसित भारत मिशन के तहत लघु तथा मध्यम किसानों की मदद हेतु मत्स्य पालन, पशुपालन तथा तटवर्ती किसानों के लिए उच्च मूल्य की कृषि को बढ़ावा देने का प्रयत्न है। पशु चिकित्सकों की उपलब्धता 20,000 से ज़्यादा बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्र में वेटरनरी और पैरा वेट कॉलेज, वेटरनरी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब और ब्रीडिंग फैसिलिटी बनाने हेतु लोन-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का प्रस्ताव है।

बजट, सबका साथ, सबका विकास के विज़न के अंतर्गत एक विकसित भारत की ओर ले जाएगा। इसके लिए किसानों की इनकम बढ़ाने, वृद्धों की देखभाल तथा इलाज की विशेष व्यवस्था करने तथा दिव्यांगजनों को मज़बूत तथा सक्षम बनाने, कमज़ोर लोगों को मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर तक पहुँचने में मदद करने, विकास और रोज़गार के मौकों को तेज़ करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। तीन नये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना प्रस्तावित है। मेडिकल नॉलेज ग्रिड की स्थापना भी प्रस्तावित है। बेहतर और नए फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अंदर कम्युनिटी के रिटेल आउटलेट के तौर पर सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट बनाए जाएँगे।

सामानों की आसान और तेज़ आवाजाही के लिए कस्टम प्रक्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। टियर 2 और टियर 3 ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, के लिए ड्यूटी टालने की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की जाएगी। यही सुविधा एलिजिबल मैन्युफैक्चरर-इंपोर्टर्स को भी दी जाएगी। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स द्वारा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में रियायती दरों पर बिक्री को आसान बनाने के लिए एक विशेष वन-टाइम उपाय का प्रस्ताव है।

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कार्गो क्लीयरेंस अप्रूवल को वित्तीय वर्ष के अंत तक एक सिंगल और इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो के माध्यम से आसानी से प्रोसेस किया जाएगा। जिन सामानों के लिए किसी कंप्लायंस की ज़रूरत नहीं है, उनका क्लीयरेंस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही तत्काल किया जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र या खुले समुद्र में भारतीय जहाज़ों द्वारा पकड़ी गई मछली पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। व्यक्तिगत उपभोग के लिए आयात किए जाने वाले सभी ड्यूटी वाले सामानों पर टैरिफ दर 20 फीसद से घटाकर 10 फीसद कर दी जाएगी। 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी। सात दुर्लभ बीमारियों को उन दवाओं, मेडिसिन और स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए भोजन, जिनका इस्तेमाल उनके इलाज में होता है, के व्यक्तिगत आयात पर आयात शुल्क से छूट दी जाएगी।

समुद्री उत्पाद, चमड़े और कपड़ा उत्पादों में, निर्यात के लिए समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उपयोग साधनों के शुल्क-मुक्त आयात की सीमा को एक फीसद से बढ़ाकर तीन फीसद किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में, बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल निर्माण में उपयोग के पूंजीगत सामानों की बेसिक सीमा शुल्क छूट को बढ़ाया जाएगा और सौर ग्लास के निर्माण में उपयोग होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी सामानों के आयात पर मौजूदा बेसिक सीमा शुल्क में छूट को वर्ष 2035 तक बढ़ाया जाएगा।

केन्द्रीय बजट 2026-27 सामाजिक संवेदना के साथ राजकोषीय अनुशासन के अंतर्गत विकसित भारत की संकल्पना रखते हुए सशक्त तथा पर्यावरण अनुकूल आधारभूत ढ़ाचें की बुनियाद पर विनिर्माण तथा कृषि को प्राथमिकता देता है। तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के मध्य यह विकसित भारत की ओर मजबूती से बढ़ते भारत का प्रयास है।

ग्राम किवलारी में संत रविदास जयंती मनाई

सोहागपुर। समीपवर्ती ग्राम किवलारी में संत शिरोमणि भक्त रविदास जी महाराज की 149वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में पुष्प अर्पित करके आरती की गई । समाजसेवी गणेश अहिरवार ने संत रविदास जी के संबंध में विस्तार से विचार रखते कहा कि संत रविदास जी ने भेदभाव मिटाने के लिए अधिक प्रयास किया था। तथा उनके स्मरण से गंगा जी प्रसन्न

होकर उनको उनके कटौती में मां कंगन उत्पन्न किया था । वहीं उनका जन्म काशी बनारस में हुआ। उनके वचन ऐसा चाहू राज में मिले सावन को अन्य चोट बड़ो सब सम रविदास रहे प्रसन्न। कार्यक्रम में की उपस्थित वक्ताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए । अंत में प्रसादी वितरण की गई। इस अवसर पर गणेश अहिवार, संतोष परमार, अशोक परमार ,रमेश अहिरवार, बादामी लाल अहिरवार ,काशीराम अहिरवार ,सुम्मी लाल अहिरवार ,भभूती लाल पर्वत सिंह, हर्ष परमार, रामखलावन, हुकम चंद ,विनोद ,शुभम परमार, हेमराज अहिरवार, आकाश बम्होरिया पहलवान बक्शी, नर्मदा प्रसाद अहिरवार, राम गोपाल, इंदल अहिरवार ,छत्रपाल, विजयपाल अहिरवार, खुशीलाल अहिरवार, गन्नू लाल अहिरवार आदि उपस्थित थे।

श्री शंभू दरबार में बुंदेली कथा वाचक का आगमन

सोहागपुर। श्री शंभू दरबार पलाश परिसर में बुंदेली कथा वाचक महंत श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज का आगमन हुआ । इस अवसर पर श्री विपिन महाराज जी ने अपने सत्संग में गौ सेवा एवं गौ रक्षा की बात कही। वहीं आपने अधिक से अधिक गौ पालन शुरू करने का आव्हान किया। इस अवसर पर गृहस्थ साधक पं प्रकाश मनमोहन जी मुद्गल ने आध्यात्म मंडल एवं श्री शम्भू भक्त मंडल की ओर से महाराज जी का शॉल श्रीफल से स्वागत वंदन किया।

स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चौहान स्मृति

अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के तृतीय दिवस में रायपुर ने शानदार प्रदर्शन करते भोपाल को पराजित किया

सुबह सवेरे सोहागपुर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय ठाकुर प्रतापभानुसिंह चौहान की स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के 61वें वर्ष के तृतीय दिवस की प्रतियोगिता अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी,एसडीओ पुलिस संजू चौहान, तहसीलदार आर के झरबड़े के आतिथ्य में जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय परिसर में संपन्न हुई। प्रथम हाकी प्रतियोगिता रायपुर बनाम भोपाल के मध्य हुआ।, जिसमें रायपुर की टीम ने कलात्मक हांकी का प्रदर्शन करते भोपाल को 4-0 से पराजित किया। भोपाल की टीम कोई भी गोल नहीं कर पाई। द्वितीय मैच में सिवनी छपारा एवं हरदा के बीच हुआ। जिसमें दोनों टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लेकिन दोनों टीम कोई भी गोल नहीं बना पाई। अंत में ट्राई ब्रेकर में 4-5 से सिवनी छपरा ने रोमांचक जीत दर्ज की। तृतीय मुकाबला में मंडीदीप की टीम ने कड़े संघर्ष में ट्राई ब्रेकर में केरला कोच्ची को एक गोल से हराया। आज के चतुर्थ अंतिम मुकाबला में सोहागपुर ने उमरिया को 5-1 हराया। प्रतियोगिता के निर्णायक की भूमिका रवी हरदुआ एवं शिवम सोनोधीया ने निभाई। सोहागपुर की शानदार जीत पर अभिनव पालीवाल एवं प्रशांत जयसवाल ने सोहागपुर टीम को रू. 2100 प्रोत्साहन राशि दी। इस अवसर पर वरिष्ठ वकील शेर खान ,भगवान सिंह पटैल, वीरेंद्र शर्मा, रमेश यादव, वकील बीके शर्मा, रूप नारायण शर्मा, हरिहर सिंह राजपूत,महाविद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष कैलाश पालीवाल, कानूलाल अग्रवाल, सचिव हमीर सिंह चंदेल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अभिलाष सिंह चंदेल, हरगोविंद पुरबिया, समिति अध्यक्ष जयराम रघुवंशी, भानूप्रकाश तिवारी, समिति सचिव एवं पत्रकार संघ अध्यक्ष पवनसिंह चौहान , नन्हू विजय छाबड़िया एजीपी शंकरलाल मालवीय, अभिषेक चौहान, सौरभ तिवारी, अभिनव पालीवाल, दादूराम कुशवाहा, अंकुश जायसवाल, किशोर काका, मनोज गोलानी , अभिषेक अग्रवाल, वकील अख्तर खान आदि उपस्थित थे। इसके पूर्व अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।

मछली के जाल में फंसा अजगर, सर्पमित्र ने जाल काटकर सुरक्षित किया रेस्क्यू

बैतूल। ग्राम रातामाटी में एक किसान के खेत के पास माचना नदी किनारे मछली पकड़ने के जाल में एक अजगर फंसा हुआ मिला। किसान मदन यादव ने खेत के पास जाल में फंसे अजगर को देखा और इसकी सूचना दी। यह खेत नदी के किनारे है, जहां अक्सर मछुआरे जाल लगाते हैं। जानकारी मिलते ही सर्पमित्र विशाल विश्वकर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अजगर करीब दो से तीन दिन से जाल में फंसा हुआ था और लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अजगर की लंबाई लगभग सात फीट थी। सर्पमित्र ने सावधानी से लकड़ी की मदद से अजगर के मुंह को काबू में किया और धीरे-धीरे जाल काटा। करीब एक घंटे की मेहनत के बाद अजगर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अच्छी बात यह रही कि जाल में फंसने के बावजूद अजगर को कोई चोट नहीं आई। इसके बाद अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। विशाल विश्वकर्मा ने बताया कि यह भारतीय अजगर प्रजाति का है, जो आमतौर पर जंगल, खेत और नदी किनारे पाए जाते हैं। ये सामान्य तौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन परेशान होने पर खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अजगर की उम्र करीब 15 साल हो सकती है।

दादा गुरुदेव के दरबार में बागेश्वर सरकार, उमड़ा आस्था का सैलाब

- **मोहनखेड़ा तीर्थ की पावन धरा पर महाकुंभ सा नजारा**

राजेश शर्मा

दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरीश्वर की पावन धरा श्री मोहनखेड़ा तीर्थ सोमवार को ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनी। धर्म धरा पर हज़ारों- हज़ार श्रद्धालुओं की उपस्थिति से आस्था का ऐसा सैलाब मानों मोहनखेड़ा तीर्थ की पावन धरा पर महाकुंभ सा नजारा दिखाई दे रहा था। दादा गुरुदेव के दरबार में बागेश्वर सरकार (बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री) की कथा व प्रवचन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई बागेश्वर सरकार की एक झलक पाने के लिए आतुर था। पंडित शास्त्री शाम करीब 4 बजे कथा स्थल पहुंचे। इसके पहले मोहनखेड़ा तीर्थ स्थित भगवान आदिनाथ व दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरीश्वर जी म.सा. के दर्शन वंदन किए। उन्होंने तीर्थ पर स्थित साधु व साध्वियों के दर्शन भी किए।

श्री मोहनखेड़ा जैन तीर्थ के ट्रस्ट मंडल ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बहुमान किया। पंडित शास्त्री जैसे मंदिर से बाहर पहुंचे वैसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देख बागेश्वर सरकार खुली जीप में सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए कथा स्थल पर पहुंचे। यहां जमकर आतिशबाजी से उनका स्वागत हुआ।

बागेश्वर सरकार ने कहा कि पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है ओर भक्ति में डूबे रहोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि बाहर से तो संसारी हो जाओ लेकिन मन के भीतर से हमेशा संन्यासी बनकर रहना ताकि जीवन में कठिनाइयों का सामना भी कर सको। दिल लगाओं तो भगवान से लगाना और दिमाग लगाओं तो काम में लगाओ जिससे आपके कार्य भी आसान हो जाए। पंडित शास्त्री ने सरल शब्द का अर्थ बताते हुए कहा कि हृदय में सरलता रखना जिससे आपके हृदय के अंदर प्रभु राम, माता सीता व लक्ष्मण तीनों विराजमान हो जाए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में धर्मांतरण ने पैर पसार रखे है लेकिन वह होने नही देंगे। क्योकि हमको गर्व है भारत की परंपरा में हम लोग दिखने में अनेक है लेकिन हम सब हिन्दू एक हैं। जैन समाज के बारे में उन्होंने कहा कि हिन्दू ओर जैन दोनों एक है। सनातन धर्म से जैन परंपरा अलग नही हैं। बागेश्वर सरकार ने कहा कि में पालीताना तीर्थ भी होकर आया हूं जहां जैन धर्म की अटूट आस्था भगवान आदिनाथ पर हैं।

बागेश्वर धाम के पंडिर शास्त्री एक घण्टे तक कथा स्थल पर रहे। में मोहनखेड़ा आता जाता रहूंगा। बागेश्वर सरकार ने सरदारपुर के दादा दयालु मंदिर का भी जिक्र किया। मंच पर बागेश्वर धाम के श्री शास्त्री का अभिनंदन रमेश गोवाणी परिवार के द्वारा किया गया। प्रसिद्ध भजन गायक अमित धुर्वे ने भजनों की प्रस्तुतियां दी तथा कॉमेडियन सुनील पाल ने भी लोगो को हंसाया। बागेश्वर सरकार के साथ मंच पर हनुमान गढ़ी अयोध्या के राजूदास जी महाराज सहित अनेक संत मौजूद रहे। साथ ही सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल भी मंच पर मौजूद रहे।

रामधुन से हुई कथा की शुरुआत – बागेश्वर सरकार की कथा सुनने के लिए अनेक जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मोहनखेड़ा पहुंचे थे। जिनके भोजन की व्यवस्था भी लाभार्थी परिवार द्वारा की गई। जैसे ही बागेश्वर सरकार कथा स्थल पर पहुंचे वैसे ही जयकारों से पांडाल गूंज उठा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने प्रवचन की शुरुआत रामधुन से की जिससे पुरा वातावरण धर्ममय हो गया। अंत मे समापन अर्जी लगवा कर किया गया। कथा स्थल पर कई एलईडी के माध्यम से लोगों ने बागेश्वर सरकार की कथा सुनी। ग्राम पिपरनी के प्रीतम ओर मोहनखेड़ा की खुशी मिश्रा ने बागेश्वर सरकार को स्कैच पेंटिंग भेंट की।

अमृत प्रोजेक्ट के तहत शहर में बनाई जा रही 4 पानी की टंकियां, सितंबर में खत्म हो गई समय सीमा

तीन टंकियों का मंथर गति से चल रहा निर्माण, एक टंकी के लिए जगह ही तय नहीं

एस. द्विवेदी बैतूल।

अमृत योजना के तहत शहर में चार पानी की टँकियों का निर्माण होना था। जिसमें से तीन टंकियों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ, जबकि एक पानी की टंकी के लिए नगरपालिका को अभी तक जगह ही नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि अमृत प्रोजेक्ट के तहत शहर में 4 टंकियां बनना हैं, लेकिन 4 महीने पहले ही समय सीमा समाप्त होने के बावजूद अभी तक एक भी टंकी का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। दरअसल शहर में जल प्रदाय के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए अमृत प्रोजेक्ट के तहत 4 अतिरिक्त टंकियां बनाई जाना है। इन टंकियों का निर्माण 11 करोड़ रुपये की लागत से होना है। बताया जा रहा है कि इस कार्य का जिम्मा गुजरात की कंपनी को सौंपा गया है। कंपनी को यह कार्य 14 सितंबर 2025 तक पूरा करना था। लेकिन चार में से तीन टंकियों का काम अभी भी अधूरा है। यह बात अलग है कि परिषद ने कंपनी को काम पूरा करने के लिए एक साल का और एक्सटेंशन दिया है। अब कंपनी को यह कार्य 14 सितंबर 2026 तक पूरा करना है। यहां उल्लेखनीय है कि अमृत प्रोजेक्ट के तहत चार टंकी बनना है, जिसमें टिकारी, दुर्गावार्ड, राजेन्द्र वार्ड और जयप्रकाश वार्ड में निर्मित की जा रही है, वहीं एक टंकी के लिए अभी तक नगरपालिका जगह की तलाश ही नहीं कर पाई है। जिससे इस टंकी का निर्माण शुरू ही नहीं हो पाया है।

टिकारी में 18.50 लाख लीटर की बन रही टंकी– अमृत प्रोजेक्ट के तहत शहर में चार नई टँकियों का निर्माण होना था। जिसमें से तीन टंकियों का निर्माण कार्य चल रहा है। सबसे बड़ी टंकी शहर के टिकारी क्षेत्र में बन रही है। यहां 18.50 लाख लीटर क्षमता की पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जबकि दुर्गा वार्ड में 7.50 लाख लीटर और राजेन्द्र वार्ड में 12 लाख लीटर पानी संग्रहण क्षमता की टँकी रहेगी। जयप्रकाश वार्ड की टंकी की क्षमता भी 7.50 लीटर रहेगी। टिकारी और दुर्गा वार्ड में टंकी निर्माण काफी पहले शुरू हो चुका है। हालांकि अभी इनका काम पूरा नहीं हो पाया है। लोगों का आरोप है कि काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। वहीं लोग गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। राजेंद वार्ड में बनने वाली तीसरी टंकी का निर्माण कार्य हाल ही में शुरू हुआ है।

एक टंकी के लिए अभी तक नहीं मिल पाई जगह– शहर में तीन टँकियों का निर्माण तो शुरू हो चुका है, लेकिन एक टँकी के लिए अभी तक नगरपालिका जमीन ही नहीं तलाश सकी है। जिसके लिए नगरवासी नपा के अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहरा रहे है। नगर के प्रबुद्धजनों का आरोप है कि प्रोजेक्ट की टाइम लिमिट खत्म होने के बाद 4 महीने भी बीत चुके हैं, इसके बावजूद जयप्रकाश वार्ड में बनने वाली टंकी का स्थान ही फाइनल नहीं हो पाया है। अब बताया जा यहा है कि टंकी के लिए दो-तीन दिन में अधिकारी जगह का निरीक्षण करने जायेगे। जिसके बाद उपयुक्त जमीन मिलने पर टँकी के लिए जमीन फाइनल करेगे। फिलहाल जो तीन टँकियों का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माण की गति भी बेहद धीमी बताई जा रही है।

चार टंकियों के निर्माण के बाद बढ़ जायेगी क्षमता

शहर में पानी की सप्लाई टंकियों से की जा रही है। शहर में 17400 नल कनेक्शन हैं, वहीं पाइप लाइन का नेटवर्क करीब 190 किलोमीटर है। फिलहाल नगर पालिका द्वारा रोजाना 10 लाख लीटर पानी की सप्लाई करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी शहरवासियों को एक दिन के अंतराल से पानी की सप्लाई की जाती है। बताया जाता है कि नगर पालिका की प्लानिंग नागरिकों को 24 घंटे पानी उपलब्ध करने की है। इसके लिए वाटर सप्लाई नेटवर्क की क्षमता में बढ़ोत्तरी किया जाना जरुरी है। वर्तमान में जो क्षमता है, उससे 24 घंटे पानी सप्लाई करना संभव ही नहीं है। यही कारण है कि यह 4 नई टंकियां शहर में बनाई जा रही हैं। इन टंकियों के निर्माण के बाद वाटर सप्लाई नेटवर्क की क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी। जिससे लोगों को संभवतः 24 घंटे पानी की आपूर्ति की जा सकेगी।

टंकियां भरने अतिरिक्त पानी की आवश्यकता

शहर में अमृत योजना के तहत पानी की टंकियों का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन इन टंकियों को भरने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। ऐसे में लोगों का कहना है कि बेहतर होता कि नगर पालिका पहले पानी का स्रोत तलाश कर उसकी व्यवस्था करती और वह निश्चित हो जाने पर टंकी का निर्माण शुरू करती। लेकिन नपा बिना किसी ठोस प्लानिग के काम करा रही है। शहर के कोठीबाजार क्षेत्र में ज्योति टॉकीज के सामने बनाई गई एक टंकी साल भर बाद में भी उपयोग में नहीं आ सकी है। इस टंकी को बने हुए करीब एक साल हो चुका है। इसके बावजूद इस टंकी को न तो कनेक्ट किया गया है और न ही एक बार भी इसे भरा गया है। लोगों का आरोप है कि नपा किसी ठोस प्लानिंग के ही कार्य शुरू कर देती है। जिसका नतीजा यह होता है कि पैसे खर्च होने के बाद भी लोगों का उसका लाभ नहीं मिल पाता है।

इनका कहना है

परिषद द्वारा तीन पानी टंकियों के निर्माण के लिए कंपनी को एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है। चूंकि निर्माण कंपनी को वर्कआर्डर लेट मिला था और सारी चीजों में देरी हुई थी। इसलिए अवधि बढा दी है। वहीं चौथी पानी की टंकी के लिए एक-दो दिन में जगह का चयन करने निरीक्षण किया जायेगा। यदि जमीन उपयुक्त पाई जाती है तो आगे की कार्रवाही कर टंकी निर्माण शुरू करवाया जायेगा।

– सतीश मटसेनिया,
सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

जेएच कॉलेज में एनएसयूआई का धरना

बैतूल। जेएच कॉलेज में बुधवार को एनएसयूआई से जुड़े छात्र-छात्राओं ने प्राचार्य कक्ष में धरना दिया। करीब एक घंटे तक चले इस प्रदर्शन में छात्रों ने कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ बढने का आरोप लगाया। छात्रों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी चौबे को ज्ञापन सौंपा। प्राचार्य द्वारा समस्याओं के निराकरण और एक समिति गठित करने के आश्वासन के बाद ही छात्रों ने धरना समाप्त किया। छात्र अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य कक्ष

में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने करीब एक घंटे से अधिक समय तक धरना जारी रखा। इस दौरान कॉलेज के कई प्राध्यापकों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे और कार्रवाई की मांग करते रहे। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के वार्षिक उत्सव के आयोजन को लेकर भी मांग रखी। इस पर प्राचार्य डॉ. चौबे ने एक प्रोफेसर समिति गठित कर इस विषय पर चर्चा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने छात्रों से वादा किया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। धरने का नेतृत्व कॉलेज एनएसयूआई अध्यक्ष रामकुमार नागवंशी ने किया। इस दौरान उपाध्यक्ष खुशी उइके, राजा बचले, जुनैद खान और अनस अंसारी सहित करीब एक दर्जन कार्यकर्ता उपस्थित थे।

वृंदावन से आज लौटेंगी फूलवती मैया, स्टेशन पर होगा भव्य स्वागत

बालाजीपुरम की पहल पर बेटा लेने गया था वृंदावन

बैतूल। जिले के आमला की वृद्ध माता फूलवती आखिर अपने घर वापस आ रहीं हैं। बालाजीपुरम की पहल पर बेटा अपनी मां को लेने वृंदावन पहुंचा और अब आज मंगलवार को उनकी वापसी है। गौरतलब है कि आमला के बांगा गांव की निवासी फूलवती यदुवंशी अपने दोनों बेटे झाडूराम और दिनेश से नाराज होकर बिना बताए वृंदावन स्थित अनिरूद्धाचार्य जी के गौरी गोपाल आश्रम पहुंच गई थीं। यहां प्रसिद्ध कथाकार अनिरूद्धाचार्य जी से उनकी बातचीत का वीडियो काफी वायरल हुआ और बैतूल का नाम आने से बैतूल को शर्मसार होना पड़ा। लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। तब भारत के पांचवें धाम श्री रूकमणि बालाजी मंदिर बालाजीपुरम बैतूल के संस्थापक सेम वर्मा आगे आए और उन्होंने फूलवती मैया के घर-परिवार का पता कर बेटों को बुलाया। छोटे बेटे दिनेश ने तो मां से मिलने से इंकार कर दिया, लेकिन बड़े बेटे झाडूराम ने सेम वर्मा की समझाइश पर मां को वृंदावन से लाने और अच्छे से रखने की सहमति दी। इसके बाद टीम बालाजीपुरम समाजसेवी सुनील द्विवेदी के साथ वृंदावन

पहुंची और यहां मां-बेटे का मिलन हुआ। अनिरूद्धाचार्य जी ने भी बालाजीपुरम की पहल की सराहना की और मां-बेटे को धूमधाम से रवाना किया। अब आज 3 फरवरी मंगलवार को दोपहर डेढ़ बजे दक्षिण एक्सप्रेस से मां-बेटा बैतूल स्टेशन के प्लेटफार्म एक पर उतरैंगे। जहां बालाजीपुरम की पूरी टीम के साथ शहर के सभी गणमान्य गाजे-बाजे के साथ स्वागत करेंगे। इसके बाद सभी बालाजीपुरम पहुंचेंगे जहां भगवान बालाजी की आरती और धन्यवाद के बाद मां-बेटे ग्राम बांगा रवाना होंगे।

आरडीपीएस में वार्षिक खेल महोत्सव आयोजित

खेल शारीरिक दक्षता के साथ नेतृत्व क्षमता, टीम भावना विकसित करते हैं : एसपी

बैतूल। उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल में डायरेक्टर श्रीमती ऋतु खण्डेलवाल के मार्गदर्शन में आयोजित दो दिवसीय खेल महोत्सव में विद्यार्थियों ने अनुशासन और खेल भावना से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 31 जनवरी को खेल महोत्सव का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन एवं प्राचार्य ने किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एस.पी. श्री जैन ने कहा कि खेल से शारीरिक दक्षता के साथ ही जीवन के महत्वपूर्ण

कौशल अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का भी विकास होता है। उन्होंने बच्चों के साथ अपनी खेलों के प्रति अभिरूचि भी सांझा की। आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल में आयोजित खेल महोत्सव के पहले दिन 31 जनवरी को ऊंची कूद, लंबी कूद, खो-खों, रस्साकशी, 100 मीटर -200 मीटर दौड़, बोरी दौड़, साइकिल रेस सहित 11 खेल प्रतियोगिताओं में 1600 विद्यार्थियों ने सहभागिता कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दूसरे दिन 1 फरवरी को फायनल मुकाबले हुए। खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पंवार, तहसीलदार पूनम साहू, एसडीओ फारेस्ट अमित खन्ना, टीआई. देवकरण डेहरिया, रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉ. अशोक बारंगा एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉ. मयंक भार्गव ने विजेता खिलाडियों को प्रमाण पत्र एवं पदक वितरित कर पुरूस्कृत किया।

संक्षिप्त समाचार

जागरूकता कार्यक्रम में छात्राओं को हाइपरटेंशन व दंत स्वास्थ्य की दी गई जानकारी

विदिशा (निप्र)। राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा में युवाओं में बढ़ती गंभीर समस्या हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तत्वाधान में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संस्था के प्रभारी प्राचार्य डॉ. मलखान सिंह के मार्गदर्शन में तथा संयोजन डॉ. शांता अहिरवार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला अस्पताल विदिशा के मेडिकल ऑफिसर एवं कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. विकास जैन ने छात्राओं एवं स्टाफ को उच्च रक्तचाप के कारण, उससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं एवं संभावित बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनियमित दिनचर्या, तनाव, असंतुलित आहार एवं शारीरिक गतिविधियों की कमी हाइपरटेंशन के प्रमुख कारण हैं। साथ ही नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, नमक का सीमित सेवन और समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जिला अस्पताल से आई डॉ. अपेक्षा जैन ने दंत स्वास्थ्य विषय पर व्याख्यान देते हुए दांतों की सही देखभाल, दांत दर्द, पायरिया और जिंजिवाइटिस जैसे सामान्य दंत रोगों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित ब्रशिंग, सही खानपान और समय पर दंत परीक्षण से दंत रोगों से बचाव संभव है। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्राओं ने अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न रखे, जिनका दोनों चिकित्सकों ने संतोषजनक समाधान किया। उपस्थित सभी ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। अंत में डॉ. संध्या जैन ने जिला अस्पताल की टीम का आभार व्यक्त करते हुए दोनों चिकित्सकों के प्रति महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया।

सोहागपुर विधायक की अनुशंसा पर 24 हितग्राहियों हेतु 2 लाख 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृति जारी

नर्मदापुरम (निप्र)। सोहापुर विधायक श्री विजयपाल सिंह की अनुशंसा पर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा विधायक स्वेच्छानुदान निधि से 24 हितग्राहियों के लिए 2 लाख 50 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोहागपुर विधायक श्री विजयपाल सिंह की अनुशंसा पर विधायक निधि से सोहागपुर निवासी श्री शेखर विश्वकर्मा को, श्री नंदकिशोर, माखननगर निवासी श्री नंदकिशोर मालवीय को, श्री मखान कीर को, सोहागपुर निवासी श्रीमती लक्ष्मीबाई अहिरवार को, सोहागपुर निवासी श्री कन्हैया लाल चौधरी को, नर्मदापुरम निवासी श्री संजू को, माखननगर निवासी श्री मोहनलाल पाल को 05-05 हजार रूपए की आर्थिक सहायता की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार माखन नगर निवासी कु. रीतिका साहू, कु. अक्षरा साहू, श्री अभिराज सिंह, श्रीमती सोमती बाई, श्री आयुष परनामे, सोहागपुर निवासी श्री भगवान अहिरवार, श्री अनिल रघुवंशी, श्री दीपक कुमार एवं श्री कृष्ण कुमार सैनी को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। माखननगर निवासी श्री राजेश अहिरवार, श्री हरि प्रसाद अहिरवार, श्री सज्जन उईके को एवं सुपाल धुर्वे को 15-15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। माखननगर निवासी कु. प्रियांशी अहिरवार, श्री विनोद कीर एवं केसला निवासी श्री सुरेश कुमार यादव को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

सीईओ जिला पंचायत ने माखननगर के ग्राम पंचायतों का किया औचक निरीक्षण

नर्मदापुरम (निप्र)। जिले में जनहितकारी योजनाओं को लेकर आये दिन जमीनी स्तर से जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। इसी तारतम्य में सीईओ जिला पंचायत हिमांशु जैन द्वारा माखननगर ग्राम पंचायत सांगाखेड़ा कला का औचक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत कार्यालय एवं शौचालय साफ सफाई व्यवस्था, ग्राम पंचायत में संधारित दस्तावेज ई-केवायसी/ मनरेगा/प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण/ स्वच्छ भारत मिशन/ करारोपण इत्यादि की गहन समीक्षा की गई। तथा पाई गई कमियों पर 15 दिवस में प्रगति अर्जित कर अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री जैन ने ग्राम पंचायत सांगाखेड़ा कला का पैदल चलकर निरीक्षण किया गया। जिसमें उन्होंने साफ सफाई, नाली की उचित व्यवस्था और करारोपण के निर्देश दिए। उन्होंने दुकानदारों से चर्चा कर करारोपण दिये जाने हेतु प्रेरित किया साथ ही कर देने से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। ग्राम पंचायत सांगाखेडाकलॉ में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों से शिक्षा के उज्जवल अवसर तलाशने के संदर्भ में मार्गदर्शन दिया। विद्यार्थियों से ए.आई. आधारित शिक्षा प्रणाली ग्रहण करने हेतु चर्चा की गई और ए.आई. के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है, इसके प्रत्यक्ष रूप से टिप्स दिए गए। साथ ही गुड़ला ग्राम पंचायत में नर्मदा नदी किनारे प्रसिद्ध सूरज कुंड स्थान पर पौधरोपण किया और स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं को कराने और घाट को सुंदर बनाने के निर्देश दिये। आजीविका मिशन का सामुदायिक प्रशिक्षण केंद माखननगर का भी दौरा किया। जिसमें आजीविका मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण ले रही दीदीयों से भविष्य में आजीविका से जीवन स्तर सदृढ करने के संबंध में चर्चा की गई एवं विकासखण्ड माखननगर में आयोजित खंड स्तरीय खेल उत्सव में भाग लिया और बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर उनका उत्साह वर्धन किया गया।

महाशिवरात्रि मेला 2026 के दौरान पचमढ़ी मार्ग पर लंबी स्लीपर बसों के संचालन पर प्रतिबंध

नर्मदापुरम (निप्र)। आगामी 06 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले महाशिवरात्रि मेला वर्षङ्क2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मेला अवधि में अधिक व्हीलबेस वाली लंबे आकार की स्लीपर कोच यात्री बसों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। उक्ताशय में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्रीमती रिंकू शर्मा ने बताया कि मटकुली से पचमढ़ी जाने वाला मार्ग दुर्गम, तीव्र चढ़ाई एवं घुमावदार मोड़ों वाला है। ऐसे मार्ग पर लंबे आकार की स्लीपर बसों का संचालन करना अत्यंत कठिन होता है और दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेला अवधि के दौरान लंबे आकार की स्लीपर कोच बसों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।

कृषक कल्याण वर्ष 2026' जागरूकता हेतु कृषि विभाग की भव्य मोटर साइकिल रैली, 150 वाहनों ने लिया भाग

विदिशा (निप्र)। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाए जाने के निर्णय के अंतर्गत जिले में जागरूकता गतिविधियों का सिलसिला निरंतर जारी है। प्रदेशभर में वर्षभर 38 प्रकार की गतिविधियों के आयोजन की रूपरेखा तय की गई है। इसी क्रम में कृषकों के सम्मान, विभागीय योजनाओं की जानकारी अंतिम किसान तक पहुँचाने तथा जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज शनिवार 31 को विदिशा में कृषि विभाग द्वारा भव्य मोटर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को रवीन्द्रनाथ टैगोर भवन से विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन, जिला पंचायत के कृषि सभापति श्री धनराज सिंह दांगी (अन्नू), विदिशा जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री वीर सिंह रघुवंशी (कक्का) एवं एसडीएम श्री क्षितिज शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

रैली दोपहर 12 बजे प्रारंभ होकर अहमदपुर चौराहा, पीतलमील चौराहा, ओवर ब्रिज, खरी फाटक रोड, कांच मंदिर, तिलक चौक, एम.एल.बी. कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, डंडापुरा, गुलाब वाटिका, न्यू बस स्टैंड, नीमताल होते हुए पुनः ओवर ब्रिज के रास्ते रवीन्द्रनाथ टैगोर भवन पहुंची, जहाँ दोपहर 1:30 बजे इसका समापन हुआ। रैली में

विधायक ने हरि झंडी दिखाकर रवाना किया

लगभग 150 मोटर साइकिलों पर विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में कृषक एवं व्यापारी शामिल हुए। रैली के अग्रभाग में कृषि रथ चल रहा था तथा डीजे पर देशभक्ति गीतों के साथ कृषि योजनाओं के प्रचार-प्रसार संबंधी नारों की तख्तियां लगाई गई थीं।

प्रमुख नारों में ÷संतुलित खाद अपनाएं, मिट्टी की जांच कराएं, पराली नहीं, अब खाद बनेगी–धरती मां की किस्मत जगेगी, बूंद-बूंद से करो सिंचाई, इसमें है किसान की भलाई, लंबी कतारों से खुद को बचाएंगे, ई-टोकन अपनाएंगे जैसे संदेश शामिल थे।

कार्यक्रम में कृषि विभाग एवं संबद्ध विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रभारी उप संचालक कृषि श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर, जिला विपणन अधिकारी श्रीमती राखी रघुवंशी, एसआरएलएम परियोजना प्रबंधक श्री संजय चौरसिया, सचिव कृषि उपज मंडी श्रीमती नीलकमल वैद्य, प्रबंधक एमपी एग्रो श्री मनोहन उइके, जिला सलाहकार डॉ. डी.के. तिवारी, सहायक कृषि यंत्री श्री राहुल खातरकर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री विशाल यादव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। इस रैली के माध्यम से किसानों को शासन की योजनाओं, आधुनिक कृषि तकनीकों एवं संसाधनों के उपयोग के प्रति जागरूक करने का संदेश प्रभावी रूप से प्रसारित किया

अपर कलेक्टर ने इछावर एवं भैरूंदा तहसील कार्यालय में एसआईआर कार्य का किया निरीक्षण

एसआईआर की प्रगति की समीक्षा कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश

सीहोर (निप्र)। अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह ने इछावर एवं भैरूंदा तहसील कार्यालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यों का निरीक्षण किया और अभी तक की कार्य प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। एसआईआर कार्य प्रगति की समीक्षा के दौरान उन्होंने मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने नो-मैपिंग वोटर्स की सुनवाई, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के निराकरण तथा दावे-आपत्तियों के निपटारे की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी सहायक एईआरओ, बीएलओ एवं संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक मतदाता का सत्यापन पूरी गंभीरता से किया जाए, किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से वंचित न रहे और अपात्र प्रविष्टियों का नियमानुसार निराकरण किया जाए। भैरूंदा तहसील के निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री सुधीर कुशवाह और इछावर तहसील के निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्रीमती स्वाति मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने ग्राम उलझावन में किया 01 करोड़ 21 लाख रूपये लागत के हाई स्कूल का लोकार्पण

शिक्षा समाज के सर्वांगीण विकास की सबसे मजबूत नींव होती है : राजस्व मंत्री श्री वर्मा

सीहोर (निप्र)। राजस्व मंत्री श्री करणसिंह वर्मा ने सीहोर तहसील के ग्राम उलझावन में 01 करोड़ 21 लाख रूपये की लागत से निर्मित शासकीय हाई स्कूल के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री करणसिंह वर्मा ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास की सबसे मजबूत नींव होती है और सरकार का निरंतर प्रयास है, कि ग्रामीण अंचलों के बच्चों को शहरों के समान गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। उन्होंने कहा कि ग्राम उलझावन में शासकीय हाई स्कूल के इस नवीन भवन के लोकार्पण से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे सशक्त रूप से अपने और क्षेत्र के उज्जवल भविष्य

कर निर्माण करेंगे। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत नए विद्यालय भवनों का निर्माण, कक्षाओं का आधुनिकीकरण, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारना और उन्हें संस्कारवान, आत्मनिर्भर तथा जिम्मेदार नागरिक बनाना है। राजस्व मंत्री ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा को केवल परीक्षा तक सीमित न रखें, बल्कि ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। उन्होंने शिक्षकों से भी कहा कि वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ-साथ नैतिक मूल्यों और अनुशासन का भी बोध कराएँ। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि अभिभावकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और बच्चों को नियमित विद्यालय भेजना तथा पढ़ाई के लिए प्रेरित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

सीएचओ का 6 दिवसीय स्किल्स लैब प्रशिक्षण 2 से 7 फरवरी तक भोपाल में

विदिशा (निप्र)। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल संभाग के निर्देशानुसार जिले के सामुदायिक चिकित्सा अधिकारियों (सीएचओ) का 6 दिवसीय स्किल्स लैब प्रशिक्षण 2 से 7 फरवरी 2026 तक भोपाल में आयोजित होगा। प्रशिक्षण में सुश्री अंजु लोधी, सुश्री महिमा मालवीय, सुश्री दीपिका गोयल एवं सुश्री सिमरन रघुवंशी शामिल होंगी।

हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाएं 13 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित की जाएगी

नर्मदापुरम (निप्र)। सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री संजय गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभाग के कमिश्नर सभी जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रो पर कड़ी निगरानी करते हुए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करें और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आदेश पोर्टल पर अपलोड करें। कक्षा दसवीं एवं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आगामी 13 फरवरी 2026 से 7 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि बोर्ड परीक्षाओं के पश्चात मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ होगा अतः मूल्यांकन का कार्य समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। जिससे परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किया जा सके। मूल्यांकन पश्चात मूल्यांकन कर्ताओं को मानदेय की राशि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। मूल्यांकन कर्ताओं के पारिश्रमिक के भुगतान में अनावश्यक विलंब न किया जाए। बोर्ड परीक्षा में पर्यवेक्षक कार्य हेतु केवल शासकीय शिक्षक ही नियुक्त किए जाएंगे। सचिव संजय गोयल ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के संबंध में भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम में साइबर सेल से संबंधित विशेषज्ञों को रखा जाएगा ताकि अनावश्यक रूप से भ्रामक जानकारियां विद्यार्थियों के बीच ना फैले। उन्होंने परीक्षा संबंधी एप की जानकारी के संबंध में बोर्ड परीक्षा केंद्रो में नियुक्त कलेक्टर के प्रतिनिधियों एवं परीक्षकों को तत संबंध में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। श्री गोयल ने निर्देश दिए की निर्धारित तिथियां तक सभी परीक्षक एवं मूल्यांकन कर्ताओं की सूची मंडल को उपलब्ध कराई जाए। कक्षा दसवीं व कक्षा 12वीं की प्रथम परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को द्वितीय परीक्षा में बैठने की पात्रता रहेगी अत विद्यार्थियों के बीच द्वितीय परीक्षा हेतु अधिकतम पंजीयन करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम, हरदा एवं बैतूल जिले के कुल 238 परीक्षा केंद्रो में कक्षा दसवीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इन 238 बोर्ड परीक्षा केंद्रो में जिला नर्मदापुरम के 78 हरदा जिले के 33 एवं बैतूल जिले के 127 परीक्षा केंद्र शामिल है। जिनमें से 10 परीक्षा केंद्र संवेदनशील एवं 13 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील श्रेणी में चिह्नित किए गए हैं। इस प्रकार संभाग के 23 संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रो में नर्मदापुरम जिले के 11 हरदा जिले के एक एवं बैतूल जिले के 11 परीक्षा केंद्र संवेदनशील एवं अति संवेदनशील श्रेणी में चिह्नित किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की नियुक्ति प्रेक्षक के रूप में की जाएगी तथा इन परीक्षा दिवसों में परीक्षा अवधि के लिए आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 को नकल रहित निष्पक्ष रूप से करने हेतु बोर्ड के निर्देशानुसार नर्मदापुरम संभाग के सभी 238 परीक्षा केंद्रों के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टर द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं।

नर्मदापुरम के 24 वनग्राम राजस्व ग्राम में होंगे संपरिवर्तित

इन वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन किया जाएगा

नर्मदापुरम जिले के 24 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन किया जाएगा उन ग्रामों के नाम है परिक्षेत्र इटारसी का वन ग्राम लालपानी, रांझी, भातना, गोलनडोह, चीचा, परिक्षेत्र सुखतवा का वन ग्राम ओझापुरा, नया झुनकर, चाटुआ, जाली खेड़ा, हिरण चापडा, परिक्षेत्र सिवनी मालवा का वन ग्राम ढेकना, आमा कटारा, गीत खेड़ा, पलासी परिक्षेत्र बानापुरा का वन ग्राम बासपानी, नयागांव, जाटमउ, बारा सेल, नापूपुरा, बैट, पीपल गोटा, घोघरा, एवं परिक्षेत्र सोहागपुर के दो गांव शामिल है।

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिले के 24 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन किया जाना है तत संबंध में नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने एवं वन व्यवस्थापन तथा विकास परियोजनाओं की अनुमति संबंधी बैठक लेकर संबंधित वन ग्रामों के पटवारी ग्राम पंचायत सचिव एवं फॉरेस्ट गार्ड को निर्देश दिए कि वह संयुक्त रूप से वन ग्रामों का भ्रमण कर केबल फाइल बनाकर एवं पटवारी एवं फॉरेस्ट गार्ड के हस्ताक्षर से फाइल तैयार कर लें। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सात दिवस के अंदर उक्त कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। कमिश्नर ने वन राजस्व एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मैदानी अमले को निर्देश दिए की वह जिले के 24 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने के पूर्व सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कर ले। परिवर्तन करने से पूर्व सभी संबंधित विभागीय अधिकारी शासन द्वारा तत संबंध में जारी 16 अप्रैल 2025 के सर्कुलर का अनिवार्य रूप से अध्ययन कर लें। कमिश्नर ने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन के पूर्व वन का ग्रामों का पूर्ण मानचित्रण, वन ग्रामों की बाहरी सीमा का निर्धारण, स्थल सत्यापन, पूरे क्षेत्र का जीआईएस के माध्यम से नक्शा तैयार किए जाने, वन अधिकार पटटेधारियों की सूची तैयार करने, नक्शे में वन अधिकार पट्टों की स्थिति दर्ज करने, ऐसे पटटाधारी जिनको वन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है उनमे उनकी जानकारी दर्ज कराने, पट्टा अथवा वन अधिकार पत्र धारी की मृत्यु हो जाने की दशा में नामांतरण, नई दावा आवेदनों को ऑनलाइन दर्ज करने, दावा आवेदनों का निराकरण करने, सामुदायिक दावों की स्थिति की समीक्षा भी की। साथ ही समय सीमा में उपरोक्त सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने वन अधिकार पट्टों से संबंधित समस्त नस्तियां वन मंडलाधिकारी कार्यालय में जमा कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में वन संरक्षक श्री अशोक कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु जैन, अपर कलेक्टर श्री बृजेंद्र रावत एवं श्री अनिल जैन, उपायुक्त विकास श्री डी एन पटेल, एसडीएम सोहागपुर सुश्री प्रियंका भलावी, एसडीएम सिवनी मालवा श्री विजय राय, एसडीएम इटारसी श्री निलेश शर्मा, एसडीएम नर्मदापुरम श्री जय सोलंकी, सभी संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वन विभाग के संबंधित रेंजर एवं फॉरेस्ट गार्ड, संबंधित पटवारी गण उपस्थित थे। बताया गया कि 24 वन ग्राम में से 19 वन ग्राम में प्रक्रिया लगभग पुरी की गई है। कमिश्नर ने निर्देश दिए की मौका भ्रमण आवश्यक है और मौके पर मुनारे मैच कर वन सीमा की बाउंड्री तय करनी आवश्यक है। उन्होंने वन ग्राम के नक्शे में वन ग्राम की बाहरी सीमा का निर्धारण करने के निर्देश दिए।

वन संरक्षण श्री अशोक कुमार ने वन एवं राजस्व विभाग के अमले को निर्देश दिए कि वह हर वन ग्राम के नक्शे की बाहरी सीमा के नक्शे का निर्धारण होने पर उस पर हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करें। यदि किसी कारण वश सर्वे नहीं हो पाया है तो सर्व अनिवार्य रूप से करें। नक्शा बनाने में जीआईएस प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए ड्राफ्टमैन की अनिवार्य रूप से सहायता लें।

सीहोर के प्रसिद्ध लकड़ी के खिलोने के साथ हाट प्रदर्शनी में सहभागिता कर रहे हैं सीहोर के शिल्पकार

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत प्रदर्शनी का आयोजन

सीहोर (निप्र)। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के पाँच पारंपरिक कारीगर 31 जनवरी 2026 तक दिल्ली हाट, नई दिल्ली में आयोजित शिल्प एवं हस्तकला प्रदर्शनी में सहभागिता कर रहे हैं। यह सहभागिता भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है तथा राज्य नोडल विभाग हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय, भोपाल द्वारा समन्वित की जा रही है।

मध्यप्रदेश से चयनित ये पाँच कारीगर प्रदेश की जीवंत एवं समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे उत्पादों में इंदौर के पारंपरिक चमड़े के खिलौने, सीहोर के लकड़ी के खिलौने, पारंपरिक लकड़ी की नक्काशीदार मूर्तियाँ, बेतूल की डोकरा (घंटी धातु) कला तथा चमड़े से निर्मित परिधान एवं एसेसरीज़ शामिल हैं। ये सभी शिल्प पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक दक्षता, सांस्कृतिक विरासत एवं क्षेत्रीय पहचान को प्रतिबिंबित करते हैं।

कारीगरों का संक्षिप्त परिचय

श्री विनोद कुमार शर्मा एवं श्रीमती सविता शर्मा, सीहोर जिले के पारंपरिक लकड़ी के खिलौना निर्माता हैं। लकड़ी के खिलौने सीहोर जिले का ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) हैं। इनके द्वारा निर्मित खिलौने सरल आकृतियों, चमकीले रंगों एवं समय-परीक्षित निर्माण विधियों के माध्यम से बच्चों एवं वयस्कों दोनों

को आकर्षित करते हैं। योजना के माध्यम से इन्हें व्यापक विपणन मंच उपलब्ध हो रहे हैं। श्री जितेंद्र, बेतूल (म.प्र.) से डोकरा (घंटी धातु) कारीगर हैं, जो पीढ़ियों से अपने परिवार के साथ इस पारंपरिक हस्त ढलाई धातु शिल्प से जुड़े हुए हैं। उनकी कृतियाँ स्थानीय संस्कृति में निहित पारंपरिक शिल्प कौशल को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनके शिल्प को राष्ट्रीय पहचान एवं बेहतर विपणन अवसर प्राप्त हो रहे हैं। श्री केदारनाथ साहू, शहडोल जिले के परंपरागत लकड़ी शिल्पकार हैं। उनकी कारीगरी पारंपरिक शिल्प कौशल को आधुनिक डिज़ाइन दृष्टिकोण के साथ संयोजित करती है, जिससे आकर्षक एवं समकालीन लकड़ी की कलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। योजना के माध्यम से उन्हें व्यापक बाजार पहुँच एवं नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। श्री प्रकाश, पारंपरिक खिलौना निर्माता हैं, जो विशिष्ट शैली के चमड़े जैसे दिखने वाले खिलौनों का निर्माण करते हैं। ये खिलौने करूरता-मुक्त सामग्रियों से बनाए जाते हैं, जबकि पारंपरिक तकनीक, बारीकी एवं फिनिश को पूर्णतः संरक्षित रखा गया है। दिव्यांगता के बावजूद उनकी निरंतर साधना एवं समर्पण प्रेरणास्पद है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से उनके उत्पादों को व्यापक बाजार एवं पहचान मिल रही है।

पूर्व आईएएस मनोज श्रीवास्तव बोले- ब्राह्मण जाति नहीं वर्ण है

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा- ब्राह्मणों को जबरन जातिवाद के लपेटे में लिया जाता है

भोपाल (नप्र)। ब्राह्मणों को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों और उन्हें जातिवादी विचारधारा में लपेटने के मामलों पर पूर्व अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों को जबरन जातिवाद के दायरे में लाया जाता है, जबकि ब्राह्मण कोई जाति नहीं बल्कि एक वर्ण है।

रिटायर्ड आईएएस और पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा कि यदि ब्राह्मणों को जाति की अवधारणा पसंद होती, तो स्वयं ब्राह्मणों के भीतर भी वैसी ही उपजातियां होतीं जैसी आरक्षित वर्गों में देखने को मिलती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्राह्मण जाति से नहीं, गोत्र से चला है।

जाति और गोत्र में फर्क बताया- श्रीवास्तव ने लिखा कि जाति और गोत्र में बुनियादी अंतर है। जाति एक सामाजिक व्यवस्था है, जबकि गोत्र पैतृक व्यवस्था है। भारद्वाज, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम और जमदग्नि जैसे गोत्र हैं। गोत्र व्यवस्था सगोत्र विवाह का निषेध करती थी, जबकि जाति व्यवस्था अपनी ही जाति में विवाह को बढ़ावा देती है।

भौगोलिक आधार पर श्रेणियां, जाति नहीं- मनोज श्रीवास्तव ने लिखा कि ब्राह्मणों के अलग-अलग भौगोलिक समूह अवश्य हैं, लेकिन वे जातियां नहीं हैं। कोंकणस्थ, देशस्थ, कान्यकुब्ज, सरयूपारीण, गौड़, कश्मीरी, सारस्वत, मैथिल, उत्कल और द्रविड़, ये सभी एक ही वर्ण के स्थानिक समूह हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इन समूहों के बीच वह दीवार नहीं है, जो दो अलग-अलग जातियों के बीच होती है। जैसे एक ही देश के अलग-अलग क्षेत्रों के लोग होते हैं, वैसे ही ये भौगोलिक पहचान हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें ऊंच-नीच या पदानुक्रम नहीं है, जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है। यदि कोई फर्क रहा भी, तो वह ज्ञान के आधार पर था, जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी, यानी जितने वेदों का अध्ययन किया गया।

'ब्राह्मणों' की बात करना कुछ लोगों की मजबूरी

श्रीवास्तव ने लिखा कि यह समझना जरूरी है कि कुछ लोगों को बार-बार 'ब्राह्मणों' की बात क्यों करनी पड़ती है। इसका कारण यही है कि ब्राह्मण एक जाति नहीं, बल्कि वर्ण है। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण इस बात का उदाहरण हैं- प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। उन्होंने कहा कि आरक्षित और अनुसूचित वर्गों को भी वैसी ही जातिमुक्तता स्थापित करनी चाहिए, जैसी ब्राह्मण वर्ण ने कर दिखाई। खुद जाति के मोह में फंसे रहना और दूसरों पर दोषारोपण करना पाखंड है। पहले स्वयं खंड-खंड में बंटे रहना बंद करें, फिर आगे बढ़ें। उन्होंने अंत में लिखा- कम ऑन, फ्रेंड्स लेट्'स डू इट। चैरिटी बिगिन्स एट होम।

नियाज खान कर चुके हैं ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग

इससे पहले पूर्व आईएएस और उपन्यासकार नियाज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि ब्राह्मण हजारों सालों से सनातन धर्म के संरक्षक रहे हैं, इसलिए उनका सर्वांगीण विकास आवश्यक है।उन्होंने ब्राह्मणों को आबादी के अनुसार आरक्षण देने और सभी योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की थी। उन्होंने लिखा था ब्राह्मण मजबूत होगा तो देश, धर्म और आध्यात्म मजबूत होगा।

भोपाल में परशुराम सेना का धरना

उपाध्यक्ष बोले-आंदोलन की रणनीति तक हम बनाते हैं, जब देने की बात आती है तो मुर्मू को ढूंढ लाते हो

भोपाल (नप्र)। भोपाल में राष्ट्रीय परशुराम सेना (ब्रह्मवाहिनी) के एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश दुबे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का सारे पूजन-पाठ हम करवाते हैं, आंदोलन की रणनीति हम बनाते हैं, समाज को दिशा देने का काम हम करते हैं। लेकिन वाहरे मोदी जी, जब इस देश में ब्राह्मणों को कुछ देने की बात आती है तो राष्ट्रपति मुर्मू का नाम ढूंढ लाते हो। दुबे ने कहा कि सत्ता यह बताकर बच निकलती है कि देश में कौन राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन उपराष्ट्रपति है, लेकिन असल सवाल यह है कि ब्राह्मण समाज को नीतिगत रूप से क्या मिला। नाम गिनाने से ब्राह्मणों के अधिकार पूरे नहीं हो जाते,।

उन्होंने आगे कहा, ब्राह्मण समाज ने देश के धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलनों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। पूजा-पाठ से लेकर संघर्ष की रणनीति तक ब्राह्मणों ने तय की है। आजादी की लड़ाई में पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी, लेकिन आज उसी समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजेश दुबे ने कहा, मीडिया में कहा जाता है कि ब्राह्मण 3 प्रतिशत हैं। मैं कहता हूं देश में ब्राह्मण 20 प्रतिशत हैं। ठाकुर, बनिया मिलाकर 35 से 40 प्रतिशत सवर्ण हैं। अगर सच्चाई सामने लानी है तो निष्पक्ष जातिगत जनगणना कराइए।

धरने का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने, सवर्ण आयोग के गठन सहित अन्य मांगों को सरकार के समक्ष रखना रहा। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी ने किया। उनके साथ राष्ट्रीय सचिव शिवाकांत तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश दुबे, हरियाणा प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष जगेश्वर शर्मा और मध्यप्रदेश अध्यक्ष विनय शुक्ला मंच पर मौजूद रहे।

सुनियोजित तरीके से ब्राह्मण समाज को निशाना बनाया- धरने को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी ने कहा कि देश में एक सुनियोजित तरीके से ब्राह्मण समाज को निशाना बनाया जा रहा है। ब्राह्मणवाद और मनुवाद के नाम पर गाली देना, संतों का अपमान करना और धार्मिक प्रतीकों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बीपा एक्ट के रूप में विशेष कानून बनाया जाए, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट जैसी सख्त धाराएं हों और आरोपियों को आसानी से जमानत न मिले। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तिवारी ने कहा कि यदि सरकार जनगणना कराना चाहती है तो कराए। उन्होंने दावा किया कि देश में ब्राह्मणों की आबादी को लेकर जो आंकड़े बताए जाते हैं, वे वास्तविकता से कम हैं। ब्राह्मण समाज ने इतिहास में मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया है और वह अपने सम्मान, बहन-बेटियों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए पीछे हटने वाला नहीं है।

11वीं की छात्रा से कार में रेप

युवक ने अश्लील वीडियो बनाया, ब्लैकमेल कर मांगे एक लाख रुपए; धर्म बदलने का डाला दबाव

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कोहेफिजा थाना क्षेत्र में एक 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ रेप, ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। शाहपुरा इलाके के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी ने कार में रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। पुलिस ने आरोपी ओसाफ अली खान (19) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। आरोपी 12वीं क्लास का छात्र है। उसके पिता डॉक्टर, जबकि मां सरकारी स्कूल में टीचर हैं। पुलिस आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर पहुंची है। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

सहेली के जरिए दोस्ती और फिर रेप

कोहेफिजा थाना टीआई कृष्ण गोपाल शुक्ला के अनुसार, आरोपी ओसाफ अक्सर छात्रा की सहेली से मिलने स्कूल के आसपास आता था। इसी सहेली के माध्यम से उसकी पहचान पीड़िता से हुई।

पिछले साल जुलाई में आरोपी ने पीड़िता को भोपाल घुमाने के बहाने बुलाया और खानूगांव के सुनसान इलाके में ले गया। वहां कार के अंदर आरोपी ने छात्रा के साथ रेप किया। विरोध करने पर उसने शादी का झांसा देकर उसे चुप करा दिया।

एक लाख रुपए की डिमांड कर ब्लैकमेल किया

आरोपी ने पीड़िता को पता चले बिना रेप के दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। कुछ समय बाद उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा से 1 लाख रुपए की मांग की। बदनामी के डर से घबराई छात्रा ने किसी तरह 40 हजार रुपये का इंतजाम कर आरोपी को दिए।

ब्लॉक करने पर दोस्तों को दिखाया वीडियो

पैसे लेने के बाद भी आरोपी की मांग जारी रही और वह बार-बार रेप करने का दबाव बनाता रहा। तंग आकर जब छात्रा ने उसे सोशल मीडिया और फोन पर ब्लॉक कर दिया, तो आरोपी ने अलग-अलग नंबरों से कॉल कर परेशान किया।

जब छात्रा नहीं मानी, तो आरोपी ने वह निजी वीडियो छात्रा के दोस्तों को दिखा दिया। इसके बाद छात्रा ने अपने मौसेरे भाई और हिंदू संगठन के लोगों की मदद से थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

धर्म परिवर्तन और नमाज का दबाव

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उस पर धर्म बदलने का दबाव डालता था। इतना ही नहीं, दबाव बनाकर उससे कई बार जबरन धार्मिक दुआएं भी पढ़वाई गईं। पुलिस ने आरोपी ओसाफ अली खान को हिरासत में ले लिया है। आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी।

नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर मछुआरों की नाव रैली

बड़वानी में 30 नावों पर निकले सैकड़ों लोग; अधिकारों के लिए सरकार से 10 मांगें

बड़वानी (नप्र)। बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत विस्थापित मछुआरों ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने किया।

मछुआरों ने कसरावद से राजघाट तक नर्मदा नदी में एक विशाल नाव रैली निकाली। इसमें 30 से अधिक नावों में सैकड़ों लोग सवार थे। रैली के जरिए उन्होंने सरकार का ध्यान अपनी लंबित मांगों की ओर आकर्षित किया। रैली के बाद मछुआरा संगठनों की ओर से कलेक्टर बड़वानी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा।

10 सूत्रीय मांग का ज्ञापन दिया जाएगा

ज्ञापन में 10 प्रमुख मांगें शामिल हैं। इनमें सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित मछुआरों को नर्मदा ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार अधिकार देना, प्रस्तावित नर्मदा माता मत्स्य सहकारी उत्पादन एवं विपणन संघ का पंजीकरण करना, पुनर्वास लाभ, आवास, आजीविका, और मत्स्य व्यवसाय सहकारी समितियों को सौंपना और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना शामिल है।

जलाशय प्रदूषण, अवैध खनन पर मछुआरों की मांगें उठीं

आंदोलनकारियों ने जलाशय में प्रदूषण, अवैध रेत खनन, क्रूज संचालन और जलस्तर गिरने से मत्स्याखेट पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने मछुआरों को किसान का दर्जा देने, केसीसी कार्ड उपलब्ध कराने, मत्स्याखेट की बंद अवधि में आर्थिक सहायता बढ़ाने और पुलिस-प्रशासन की ओर से उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई की मांग भी की।

मछुआरों के अधिकार नहीं मिले, आंदोलन तेज होगा

मेधा पाटकर ने कहा कि नर्मदा घाटी के मछुआरे विस्थापन के सबसे बड़े पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें वर्षों बाद भी उनके कानूनी अधिकार नहीं मिले हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस नाव रैली और जल भरो आंदोलन में बड़वानी, धार, खरगोन और अलीराजपुर जिलों के बड़ी संख्या में मछुआरा परिवार शामिल हुए।

भोपाल जीआरपी की बड़ी कार्रवाई

ट्रेन में चोरी करने वाला फॉरेन रिटर्न बीटेक पास चोर गिरफ्तार, 7 लाख के सोने के आभूषण बरामद

भोपाल (नप्र)। रेल यात्रियों को निशाना बनाकर ट्रेनों में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को जीआरपी भोपाल ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फॉरेन रिटर्न और पुणे यूनिवर्सिटी से बीटेक पास है, जो ऑनलाइन वेटिंग गेम की लत और पैसों की हार के बाद आर्थिक तंगी में आकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। आरोपी के कब्जे से करीब 7 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं।

जीआरपी भोपाल के अनुसार, आरोपी की पहचान प्रांजल दीक्षित (36), निवासी देव स्थान, लखनऊ के रूप में हुई है। वह ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहे यात्रियों के सिरहाने रखे पर्स को निशाना बनाता था।

ऐसे हुआ खुलासा- 20 जनवरी 2026 को आगरा निवासी अफशा बेगम ट्रेन से आगरा से मुंबई जा रही थीं। भोपाल स्टेशन पर किसी अज्ञात बदमाश ने नींद का फायदा उठाकर उनका पर्स चोरी कर लिया। पर्स में सोने की चेन, झुमके, अंगूठी, 35 हजार रुपए नकद और जरूरी कागजात थे। मुंबई पहुंचकर पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। गंभीरता से लेते हुए जीआरपी भोपाल ने अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।

200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले- जांच के दौरान टीम ने करीब 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। लगातार निगरानी और रोड मैप के विश्लेषण के बाद आरोपी को 30 जनवरी 2026 को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में उसने न सिर्फ इस वारदात, बल्कि जीआरपी भोपाल क्षेत्र के चार मामलों में चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि चोरी से मिली नकदी वह ऑनलाइन गेमिंग में खर्च कर देता था।

क्या-क्या बरामद हुआ

आरोपी के पास से मंगलसूत्र का पेंडल, सोने की दो चेन, एक जोड़ी झुमके, दो लेडीज अंगूठियां समेत कुल करीब 7 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं।

आपराधिक रिकॉर्ड

आरोपी के खिलाफ जीआरपी भोपाल थाने में धारा 305(सी) और 305(2) बीएनएस के तहत चार मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लिया गया है और अन्य आपराधिक गतिविधियों की जांच जारी है।

भोपाल के जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में कानूनी क्लिनिक शुरू

पैरालीगल वालेंटियर्स और पेनल लॉयर्स का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया

भोपाल (नप्र)। भोपाल में नालसा वीर परिवार सहायता योजना के तहत प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में पैरालीगल वालेंटियर्स और पेनल लॉयर्स का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां कानूनी क्लिनिक की शुरुआत सोमवार को की गई। इस दौरान जिला नायधीश सचिव सुनीत अग्रवाल ने बताया कि इसका उद्देश्य सशस्त्र

बलों के परिवारों के लिए कानूनी सहायता प्रदान कराना है। वीर परिवार सहायता योजना 2025 की शुरुआत 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर की गई थी। यह योजना विशेष रूप से सशस्त्र बलों के परिवारों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

योजना के मुख्य विवरण- सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और उनके आश्रित परिवारों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करना। यह एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है, जिसे कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई 2025) पर श्रीनगर में लॉन्च किया गया। भोपाल में भी इसके कानूनी क्लिनिक सैनिक बोर्डों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं।

लीगल एड सुनिश्चित करती है योजना- यह योजना संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद या अन्य कानूनी मामलों में कानूनी प्रतिनिधित्व और सहायता सुनिश्चित करती है, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात जवान तनावमुक्त रह सकें। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। जहाँ पैनल वकील और पैरा-लीगल वालंटियर्स सहायता प्रदान करते हैं। यह योजना सुनिश्चित करती है कि सैनिकों के परिवार को कानूनी मामलों में अकेले संघर्ष न करना पड़े।

मंत्रियों को समस्याएं बताने वाले कार्यकर्ता ही नदारद

राज्य सरकार के मंत्रियों के द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को तवज्जो नहीं देने की शिकायतों को दूर करने संगठन की पहल सफल नहीं होती दिखती हैं। हर सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में कोई न कोई दो मंत्री कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने पहुंच रहे हैं लेकिन समस्याएं बताने वाले कार्यकर्ता ही नदारद हैं। इसकी मुख्य वजह तो यह है कि मंत्रियों के प्रदेश कार्यालय में बैठने को लेकर कोई तय कार्यक्रम नहीं है। कौन सा मंत्री बैठेगा यह संगठन तय नहीं कर पा रहा है। ड्यूटी लगने पर मंत्रीगण तो प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने बैठ रहे हैं लेकिन समस्याएं किस की सुने, कार्यकर्ताओं का टोटा है। आज उप मुख्यमंत्री जगदीश देवडा और मंत्री गौतम टेटवाल पार्टी कार्यालय करीब दो घंटे बैठे लेकिन गिनती की कार्यकर्ता मंत्रियों से मिलने पहुंचते है। प्रदेश कार्यालय रूटीन में आने वाले कार्यकर्ता जरूर मिल जाते हैं लेकिन राजधानी भोपाल के ही अधिकांश पार्टी कार्यकर्ता मंत्रियों के समक्ष समस्याएं ले जाना में अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। जानकारों का कहना है कि कार्यकर्ता भी सत्ता की मलाई में समस्याएं बताना भूल गए हैं और अपने कार्यों में व्यस्त हैं।

मोहन का मंत्रालय
आशीष चौधरी

आशीर्वाद या विकेट गिरेगा

राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि क्या कांग्रेस का कोई विकेट जल्द गिरेगा। पिछले दिनों एक यात्रा के दौरान सरकार के मुखिया की नजर एक विधायक पर पड़ी। सरकार ने भी पूरी उदारता दिखाते हुए सिर पर हाथ रख दिया। विधायक ने अपना मांग पत्र भी दिया। सरकार ने पूरा भरोसा दिलाया। तब से कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है कि क्या माननीय वक्त आने पर पाता बदल लेंगे। हालांकि विधायक यह जरूर कहते नजर आए कि उन्होंने ने सरकार ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यो के लिए आशीर्वाद मांगा था तो सरकार ने इसकी कोई कमी नहीं की और विकास कार्यों को जल्द से जल्द मंजूर कराने का आशीर्वाद स्वरूप हाथ रखा।

दो नेताओं का पॉवर गेम

मप्र में आने वाले दिनों में कभी बेहद कद्दावर रहे दो नेताओं का पॉवर गेम देखने मिलेगा। दोनों ही नेता इन दिनों अपने-अपने आयोजन के लिए बेहद सक्रिय हैं और आयोजन को भूतो न भविष्यति बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इन दोनों ही नेताओं के बारे में ये भी संयोग ही है कि ये पिछले कार्यकाल तक बेहद पॉवरफुल थे लेकिन अभी राजनीतिक वर्चस्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दोनों के ही आयोजन में धर्म जुड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि उनके इस सद्कार्य का भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।

मंत्री से करा दिया खेला

राजधानी भोपाल नगर निगम के एक वार्ड अधिकारी को पिछले दिनों मंत्री ने कार्यालय समय पर नहीं पहुंचने के कारण मौके पर ही सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के बाद अब नगर निगम में चर्चा है कि आखिर मंत्री से अधिकारी को निलंबित करने का खेला क्यों कराया गया। अंदर की बात यह है कि आज तक तो आपने पार्षद पति सुना होगा लेकिन यहां पर पार्षद भाइयों का दबदबा है। पार्षद भाइयों के कामकाज में बाधा बनने की वजह से अधिकारी पर निलंबन की गाज गिर गई। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि पार्षद भाइयों ने क्षेत्र में छोटे-मोटे ठेले व गुमटी लगाने वालों से अवैध वसूली कर दी है और वह इस काम में नगर निगम के अधिकारी के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मंत्री से अधिकारी के समय पर आफिस नहीं पहुंचने की शिकायत कर दी और पार्षद भाइयों ने मंत्री से अचानक कार्यालय का निरीक्षण कराकर खेला कराने में कोई चूक नहीं की।